साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार

Website: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 7 अंक 22 प्रति सोमवार इंदौर, 7 जनवरी से 13 जनवरी 2013 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

क्या सच है कसाब को फांसी दी गई... या जिंदा भगा दिया... कहां है वीडियो?

जनता को खुश करने व सरकार बचाने का नाटक

आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान, उनका गृहमंत्री सब क्यों चुप रहे?

भारत की कांग्रेस और उसका संप्रग गठबंधन गिरोह भ्रष्टों और जालसाजों की फौज मुस्लिम वोट प्रेमी है। फिर काग्रेस उसका संरक्षण गठबंधन अपनी कमाई, कमीशन और येन-केन प्रकरण सत्ता हथियाने के लिए कोई भी छल, कपट, जालसाजी, षड्यंत्र, कानूनों का बनाना, समाप्त करना यहां तक कि इन शूकरों को संविधान संशोधन से भी कोई परहेज नहीं है तो फिर ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि 26/11 को इस 70 नागरिकों को भूनने, 300 से ज्यादा को घायल करने के इस आतंवदी हमले के अपराधी को जिस पर रुपए 25 लाख से ज्यादा सुरक्षा पर खर्च किए जा रहे थे। अचानक फांसी पर लटका देंगे।

मीडिया के सभी चैनलों के कैमरे सरकारी तौर पर जो महाराष्ट्र सरकार के नाटक का हिस्सा था वही सुना रहे थे और भावपूर्ण की येरावदा जेल के बंद दरवाजे तक जा रहे थे। ये सारा नाटक भारत की केन्द्रीय सत्ता में बैठे डकैत कांग्रेसी को मिले विदेशी प्रत्यक्ष निवेक के मोटे कमीशन के लिए भारत में फुटकर व्यवसाय के शापिंग माल खोलने की अनुमति पर होने

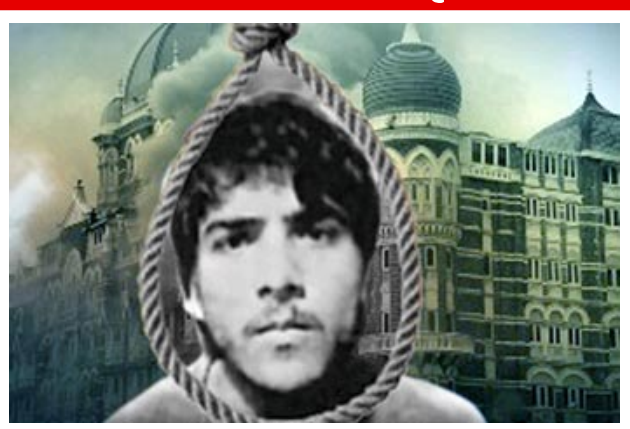

वाली लोकसभा में सरकार बचाने के लिए था, इसमें वे इस कसाब की फांसी के नाटक से कामयाब भी हुए। यदि वे कसाब की फांसी को झूठी कहानी नहीं गढ़ी जाती तो सीधे ही जनता का ध्यान इन कांग्रेसी गिद्धों की धूर्तता पर रहता जो अगले चुनाव में जीतने के लिए घातक होता।

जो प्रधानमंत्री 26/11 की इतनी बड़ी घटना के बाद 26 जनवरी पर पाकित्सान के खिलाफ भाषण न देना पड़े 23 जनवरी को अचानक हॉस्पिटलाइवर्ड हो और राष्ट्र को बताया जाए कि देश के प्रधान मंत्री की बायपास सर्जरी के लिए भर्ती किया गया है उसकी 28 जन. बाइपास भी हो जाए तो और वो चलने फिरने लगे। उन धूर्तों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कसाब को फांसी पर लटका कर अपना मुस्लिम वोट बैंक उजाड़ेंगे। पाकिस्तान को नाराज करेंगे उसने 70 तो क्या 700 भी मार डालता तो इनकी औकात नहीं कि उसको ये फांसी पर लटका देते। यदि इतने ही ईमानदार थे तो उसकी सुरक्षा पर ही 250 करोड़ से ज्यादा क्यों बर्बाद किए। सर्वोच्च न्यायालय से सजा यथावत रखने के पश्चात ही क्यों फांसी पर नहीं लटकाया गया, क्योंकि उसकी इतनी जरूरत नहीं थी,

(शेष पेज 5 पर)

पूंजीवादी शोषण, बेरोजगारी से उपजी कुंब ले डूबेगी सं. रा. अमेरिका

सो.रूस की तरह बिखरेगा अमेरिका

दुनिया की महाशक्ति अमेरिका बिखराव के कगार पर आखड़ा हुआ है, अमेरिका के 1776 के संविधान के स्वतंत्रता संबंधी घोषणा पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जब भी अमेरिकी राज्यों की जनता चाहेगी उसे राजनैतिक बंधन से मुक्त होने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। अमेरिका के बीस राज्यों लुसियाना टेक्सास मोंटाना, नार्थ डिक्रोश, इंडियाना मिसीसीपी, केंटु की, नार्थ केरो लिना, अलबामा, फ्लोरिडा, जार्जिया, न्यू जर्सी, कोटोरोडो, आरेगन, साउथ केरो बीना, टेनिसी मिशीगन, न्यू यार्क व अकोन्सस आदि है। इन राज्यों ने अमेरिकी सरकार को आवेदन दिया कि उसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से शांतिपूर्ण ढंग से वापसी की आज्ञा प्रदान करें। अमेरिकी कानून में प्रावधान है कि अलग होने संबंधी आवेदन

भारत में बढ़ता पूंजीवादी शोषण से उपजी कुंठा, देश की बर्बादी का कारण बनेगी

कर जवाब 7 दिन में देना होता है। अेमरिकी जालसाज बहुराष्ट्रीय कं. के पूंजीवादी क्षेत्रण में साथ अमेरिका की वित्तीय अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती चली जा रही है। विश्व बैंक और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो यथार्थ में उसकी घरेलू संस्थाएं हैं, जिनका उद्देश्य विश्व के प्राकृतिक साधन सम्पन्न राष्ट्रों को विकास के नाम कर्ज बांटना, वहां की सरकारों, मंत्रियों और अधिकारियों को भ्रष्ट बताकर धन वापसी और ब्याज की वसूली के लिए शर्तों में उलझा कर वहां के प्राकृतिक साधनों पर कब्जा कर कमाई करना बहुराष्ट्रीय कं. के पैर जमाता रहा है। दोनों संस्थाओं से कर्ज लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का झूठा दावे करता रहा है, जबकि उसके ये सारे दावे केवल चुनाव जीतने के शिगूफे थे, उसकी आर्थिक स्थिति सन् 2005 के बाद से लगातार बिगड़ती रही, उसकी बहुराष्ट्रीय कं. केवल लाभ के लिए काम करती रही है। जहां मंदी के कारण घाटा होना शुरू हुआ। उन्होंने सब पर ताला बंदी करना शुरू कर दी। दूसरी ओर उसके विश्व व्यापार संगठन का मुद्रा जो उसने दुनिया के उन देशों को फांसने के लिए बनाया था जो प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। (शेष पेज 6 पर)

लाखों करोड़ के घोटाले होते हैं, हर दिन...

प्र.मं.का. विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार व साजिशों का अड्डा

125 करोड़ जनता के साथ हर कदम छल, कपट, वसूली, जनहितों का बलात्कार

भारत की 125 करोड़ लोगों के भविष्य का निर्धारण उनके सुख, समृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, लूट, जालसाजियों का अड्डा बन चुका है। जिस पर देशी-विदेशी पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के साथ ही अमेरिका और युरोपीय देशों के जासूसों का कब्जा है। सबका उद्देश्य इस राष्ट्र के प्राथमिक संसाधनों से लेकर राष्ट्र के 125 करोड़ लोगों के शोषण और दोहन के माध्यम से अपने हितों का संधान और सुरक्षित करना है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाणों को भले ही इस राष्ट्र का टुकड़खोर दृश्य और श्रण्य प्रचार-प्रसार माध्यम

अपने हितों के साधन में जनता को प्रदर्शित और प्रकाशित न ही करें तो भी कांग्रेस अंग्रेजों की अवैध औलाद जिसे जाने से 62 वर्ष पूर्व पैदा करके छोड़ गए थे वह और उसके सहयोगी टुकड़खोर सपा, बसपा, तृणमूल, टीएमसी, एनसीपी, बीजू जनता दल व अन्य कई छोटे क्षेत्रीय दल जो वर्तमान सत्ता संचालन में शामिल होकर जनता को महसूस करवा रहे हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय में विराजा मनमोहनसिंह के लिए इस देश का 125 करोड़ जनता कीड़े-मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं, वो इसी जनता के दम पर उस कार्यालय में प्रधानमंत्री का दाखिला संभाल रहा है।

(शेष पेज 5 पर)

कांग्रेसी गिद्धों की गैस की दुर्लभता से लकड़ी जलाने का चलन बढ़ा

गैस में अनुदान के नाम फैला रहे आतंक

पूरी सत्ता अंबानी बंधुओं की कठपुतली बन जनता का घोर शोषण कर रही है

राष्ट्र में कांग्रेसी गिद्ध सत्ताधीशों का इतिहास रहा है, जनता को भ्रमिक कर उसे रोजमर्रा की वस्तुओं को दुर्लभ बनाकर जनता को आतंकित करना। सत्ता के मद में लूटपाट, भ्रष्टाचार, वसूली, अत्याचार, शोषण करना, आतंक भय, दहशत, फैलाना ताकि जनता इन धूर्त श्वानों के विरुद्ध आवाज न उठा सके। 1970-80 के दशक तक जनता गेहूं, शक्कर, दाल-चावल, मिट्टी का तेल आदि तक राशन की दुकानों में घरों लाइनों में खड़े रहने के बाद दिया जाता था, इन लाइनों में खड़ा रखने की प्रथा को 1972-78 में सत्ता में आई जनता पार्टी ने पहली बार अंत किया था। अन्यथा 1980 के पूर्व तक निम्न मध्यमवर्गीय से लेकर गरीबों तक सबकों लाल सड़ा गेहूं, लकड़ा-शैला चावल भी घंटो की लाइन में खड़े होने के बाद ही नसीब होता था। तब भी कांग्रेस हर अच्छी वस्तु यथा, शक्कर गेहूं, तेल, चावल, दाल से स्कूटरों-कारों तक का निर्यात करके उस समय करोड़ों रुपए कमीशन डकार जाती थी और जनता को दुनिया का सबसे गंदे शक्कर पीली सल्फर, गेहूं रशियन लाल गेहूं यहां की जनता को बंटवाती थी, बिजली, पानी, फोन आदि के कनेक्शनों के नम्बर 10-20 वर्षों के बाद मिलते थे, ये आतंक कांग्रेसी शूकरों ने 1986 से 1998 तक फैला रखा था।

अब जब दूसरी बार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की जालसाजी से जीती कांग्रेस ने फिर वही आतंक, शोषण और अत्याचार का तांडव फिर से फैलाना शुरू कर दिया है। अब आतंक का हथियार पेट्रोल, डीजल, गैस, शिगूफा है अनुदान देकर पेट्रोल, डीजल और गैस पर सरकार जो अनुदान दे रही है। उसको समाप्त करना। जिस अनुदान का कांग्रेसी गिद्धों का सरकार मनमोहनसिंह रोना-रोता है और दलीलें देता है, तो ये इसे देश की जनता को ये बताएं कि ये हरामखोर ये अनुदान अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से दे रहा है या सोनिया अपने मायके इटली से बुलवा कर जनता को बांट रही है।

(शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

हर सत्ताधीश बलात्कारी

स्वहितों के लिए जनहितों से बलात्कार

दिल्ली में छात्रा चलती बस में कुछ लड़कों ने शराब के नशे में बलात्कार करने के परिणाम स्वरूप युवाओं का आक्रोश फूटा और विजय चौक में शक्ति प्रदर्शन कर बलात्कारियों की फांसी की मांगी की। यह तथ्य दुनिया में छा गई। युवा पीढ़ी के इस आक्रोश प्रदर्शन और गुस्से को देखकर अधिकांश मध्यतम और बुजुर्गों को अत्याधिक खुशी हुई कि चलो बलात्कार के प्रति युवा पीढ़ी ने आक्रोश का प्रदर्शन किया। अब वह दिन दूर नहीं जनहितों के साथ अपने मोटे कमीशन के लिए हर सत्ताधीश जो बलात्कार करता है, कभी इसके विरुद्ध भी युवा पीढ़ी समझने पर आक्रोशित होकर आवाज उठाएगी।

केन्द्रीय सत्ता हो, राज्यों की सत्ताएं हों, नगर निगम पालिकाओं से लेकर पंचायतों की सत्ताएं क्यों न हों। सत्ता में बैठा हर सत्ताधीश जिस जनता ने उसे चुनकर सत्ता सौंपी होती है, जनहितों के साथ अपने स्वहितों के लिए कानून बनाकर, लागू कानूनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और उसके शब्दों की व्याख्या का बलात्कार करके जन हितों का बलात्कार पिछले 65 वर्षों से बलात्कार करता है। उस पर कानूनी बलात्कार हेतु उस पर कभी वह खाद्य सुरक्षा कानून बनाकर मोटा कमीशन एंठने के लिए विदेशी निवेश का फुटकर व्यवसाय में लागू करता है तो कभी पेंशन बीमा में तो कभी वोट पाने के लिए संविधान की समता और मूलभूत सिद्धांतों का बलात्कार करके 22 प्रतिशत जनजातियों को 60 प्रतिशत आरक्षण लागू करता है। जिन सवर्णों से सबसे ज्यादा आयकर बिक्री कर कस्टम और एक्साइज वसूल करता है। उसको अपने वोटों की खातिर उनके उस धन से आदिवासियों के अरबों रुपए का धन खर्च करने के नाम पर स्वयं हजम कर जाता है तो कभी उन्हीं सवर्णों को जो शासकीय सेवाओं में हैं उनको एक ही पद 30-35 साल तक सड़ाकर उनके कनिष्ठों को वरिष्ठ बनाकर सारी पदोन्नतियां उनके खाते में डाल देता है। इस प्रकार 64 वर्षों से उनके अधिकारों के साथ धन के साथ न केवल कांग्रेस वरन् भाजपा भी उसमें शामिल होकर 40 करोड़ सवर्णों के हितों के साथ बलात्कार करती है। टाटा, बिरला, अंबानी, भारती व अन्य पूंजीपतियों और उद्योगपतियों बिल्डरों, कालोनाइजरों के साथ मिलकर करोड़ों किसानों की जमीन बलात छीन कर मोटा कमीशन डकार उनकी उगलती धरती पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाती है। जब किसान इसके लिए आंदोलन करते हैं तो अपने उन बलात्कारों को जायज ठहराकर उन पर पुलिस से लाठियां, आंसूगैस के गोले और गोलियां चलवाकर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाती है। फिर हर सत्ताधीश ऐसे आंदोलनों को कुचलकर बड़ा प्रसन्न होता है। यह सत्ताधीशों का जनता के साथ बलात्कार ही था।

हर बलशाली निर्बल पर अपने हितों के साधने में अपने बल दल का प्रयोग कर जब अफनी इच्छाओं को पूरा करने का हर प्रयास बलात्कारी की श्रेणी में आता है। चाहे वो यौनाचार हो. फलोकाचार हो, शिष्टाचार, व्यापार हो, अनाचार हो, दुरुचार हो सभी बलात्कार की श्रेणी में ही गिने जाते हैं।

सत्ताधीशों का बलात्कार, समरथ को नहीं दोष गुसई की श्रेणी में आता है। चाहे वो फिर गैस सिलेंडर में झूठे अनुदान का रोना रोकर, पेट्रोल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने या उसमें भी अनुदान का आड़ लेकर महंगाई लादना भी जनता के कंधों पर चाहे वो मोटा कमीशन डकारने, अंबानी बंधुओं को फायदा पहुंचाने के षड्यंत्रों की चाल हो। यर्थाथ में जनहितों का बलात्कार ही है।

लोकतंत्र में हर चुना गया या शासकीय पदों पर बैठा हर अधिकारी जो जनहितों को बलाए ताख रखकर अपने हितों के साधन में कानूनों का बलात्कार करके ही भ्रष्टाचार कर धन उगलता है। फिर सत्ताधीश, जनहित का वह धन समेटकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से विदेशों में जमा करवा देता है। अर्थात जनता से जनहितों के नाम पर बलात्कारों की वसूली की गई, फिर जनहितों के नाम पर योजनाएं बनाकर हजारों करोड़ का धन आवंटित किया गया। धन का कागजों पर झूठी कार्रवाई दिखाकर बलात ही धन हड़प लिया गया। इस कार्य में कितनी बार जनता का जनहितों के नाम सत्ताधीशों ने बलात्कार किया।

कांग्रेस को सत्ता चलाने के लिए आतंकवाद आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलवाना ताकि जनता और प्रसार माध्यमों को ध्यान बलात बंटवाकर अपने कुकर्मों से ध्यान हटाने कुकर्मों को अंजाम देना। बाद में बलात हिन्दु संगठनों को बदनाम करके हिन्दुओं को गिरफ्तार करके बलात दहशत फैलाने, दंगा फसाद करवाना, कांग्रेस का शोक और हथियार रहा, जिसका वो बलात प्रयोग करती रही है।

कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा आदि अधिकांश राजनैतिक पार्टियों में अधिकांश नेता हिन्दु होने के बाद भी हिन्दुओं के साथ खासतौर पर अगड़ो के साथ दोगला व्यवहार करते रहे हैं या अगड़े हिन्दुओं के साथ अपने वोट में बलात ही संशोधन करना भी इस राजनीतिज्ञों का बलात्कार ही तो है, पर वो सत्ताधीश हैं। शासक है इसलिए वह जायज बलात्कार है।

सरपंच गांव की जनता के साथ जनपद अध्यक्ष व सचिव पद की जनता के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और सचिव जिले की जनता के साथ जिलाधीश, जिले की जनता के साथ, आयुक्त संभाग की जनता के साथ, मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के साथ, प्रधानमंत्री 125 करोड़ आबादी के साथ, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के साथ मिलकर स्वहित साधनेके लिए, दूसरी ओर उन पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से मोटा कमीशन डकार कर जनता और जनहितों के साथ जो बलात्कार कर रहे हैं। इके विरुद्ध भी हमारी युवा पीढ़ी को आवाज उठानी होगी। फिर विजय चौक पर इकट्ठे होकर युवाओं को हल्ला बोलना ही पड़ेगा वरना ये सत्ताधीश बलात्कारी हर कदम मोटा कमीशन डकार जनहितों के साथ बलात्कार करते हुए देश को गुलाम बनाने की साजिश करते आ रहे हैं और आवाज नहीं उठाई गई तो गुलाम बनाने से भी नहीं चुकेंगे अन्यथा बिजली, पानी, सड़कें सब ही विदेशों को सौंपने पर तुले हैं।

50000 हजार से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के साथ भाजपा का धोखा

20 से 40 वर्षों तक नियमित, स्वार्थों के चलते घोषित मजदूर

श्रम कानूनों की धज्जियां स्वयं सरकार उड़ा रही, मुफ्त में घरेलू काम के लिए

म.प्र. सरकार के 100 से ज्यादा विभागों में 1980 से लेकर सन् 1995 तक शासकीय कार्यों के लिए रखे दैनिक वेतन कर्मचारियों जो शिक्षित अर्ध शिक्षित या अनपढ़ थे, सरकार के अधिकांश विभागों जिसमें न केवल लोक निर्माण, लोक स्वा. यांत्रिकीय, जल संसाधान, नर्मदा घाटी, विकास प्राधिकरण, कृषि, उद्यानिकी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी विभाग जिसमें प्राथमिक स्वा. केन्द्रों से लेकर जनपदों जिला चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों आदि में जिलाधीश कार्यालयों से लेकर जनपदों, पंचायतों में रेशम केन्द्रों, मतस्य पालन, खनिज वन, ग्रामीण यांत्रिकीय प्रदेश के सभी नगर निगमों, पालिकाओं परिषदों नगर विकास प्राधिकरणों आदि अधिकांश विभागों में कार्य कर रहे 50000 हजार से ज्यादा दैनिक मजदूरी पर कार्यरत यर्थाथ में स्थायी कर्मचारी जिन्होंने इसी आशा में 40 से लेकर 15 वर्ष तक की जिन्दगी यहीं पर 8 से 12 घंटे नियमित कर्मचारी का दर्जा देगी। इसमें से अधिकांश की नियुक्तियां अर्जुनसिंग के मुख्यमंत्री काल से शुरू की गई थी जो अभी तक अधिकांश विभागों में कार्यरत है। इसमें अभी तक वे ही कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं थे। दूसरी ओर इसमें से अधिकांश जो पढ़े-लिखे थे, वे बेचारे बाबुओं और सहायकों के रूप में अधिकांश नियमित कर्मचारियों से न केवल ज्यादा काम कर रहे हैं। वरन् कम्प्यूटर चलाने से लेकर शासकीय वाहनों को भी वर्षों से चलाने के बाद भी इन शूकरों की फौज प्रशासनिक अधिकारियों, संचालकों जो स्वास्थ्य मंत्रालय, गलोक निर्माण, लोक स्वा. यांत्रिकीय, जल संसाधन, कृषि उद्यानिकी में बैठे हैं। उन्हें 40 से 15 वर्ष सेवाओं के बाद भी नियमित नहीं करना चाहते। इसके पीछे का भयावह सच यह भी है कि अधिकांश इंडियन एब्यूसिंग सर्विस या आईएएस जैसे महा मक्कार चालबाज, जालसाज, धुर्तों को यर्थाथ में एक अरदली रखने की पात्रता होने के बाद भी ये हराम खोरों की फौज इनको आवंटित शासकीय और गैर शासकीय आवासों पर भी 5 से 25 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से काम लेने की आदतन अपराधी शासकीय काम है, जिन वेतन शासन देता है काम ये अपने घरों पर लेते हैं। यदि इन्हें नियमित कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक है सारे नियम-कायदे, सरकारी तौर तरीके से इन पर भी लागू हो जाएंगे।

फिर इनसे 14 घंटो तक नियमित कार्य नहीं करवाया जा रहा सकेगा जो अभी तक ये दैनिक वेतन भोगी होने की मजबूरी में कर रहे हैं। बेशक ये दैनिक वेतन भोगी केवल आईएएस के यहां पर ही नहीं वरन् अधिकांश इंडियन फॉरेस्ट ईटिंग सर्विसेज बनाम आईएफएस के यहां से लेकर सभी जिलाधीशों, सहा. उप जिलाधीशों, तहसीलदारों केबिनेट के अधिकांश मंत्रियों के बंगलों पर से लेकर महापौरों, पार्षदों के घरों, अधिकांश संचालकों, प्रमुख अभियंताओं, मुख्य अभियंताओं से लेकर सहायक मंत्रियों, डॉक्टरों के बंगलों, शासकीय डॉक्टरों के व्यक्तिगत क्लीनिकों, नर्सिंग होम्स मे, निगमों, निकायों के अध्यक्षों के घरों, बंगलों पर, प्रबंध संचालकों के घरों और बंगलों पर, मुख्यमंत्रियों के बंगलों पर साफ-सफाई से लेकर फोन अटेंडर, वाहन चालक, भोजन व्यवस्था इन सारे हरामखोर अधिकारियों और नेताओं की पलियों, बच्चों की सेवा में, बाजार घुमाना, स्कूल-कॉलेज लाना लेजाना, उनके रिश्तेदारों की सेवा, इन हरामखोर धूर्त अधिकारियों की पार्टियों शादी-ब्याह, रंगरैलियों में ये बंगलों, आमोद-प्रमोद स्थलों पर दारू-शारू से लेकर मेहमानों को संभालने में भी रात्रि में 2-3 बजे तक सिर झुकाकर सेवाएं देने के लिए मजबूर हैं। इसलिए ये शूकर जासलाज मंत्रियों, अधिकारियों की फौज इन्हें नियमित करना नहीं चाहती। क्योंकि अब ऐसे कोलू के बैल दैनिक वेतन भोगी रुपए 3000-4000 के वेतन में तो नहीं मिलेंगे। जो इनकी हर बत्तमीजी को झेले। फिर भी 9 से 14 घंटे काम करके भी हाथ जोड़कर खड़े रहे। अधिकांश धूर्त आईएएस, आईएफएस व उच्चस्तरीय संचालक, उपसंचालकों को प्रमुख अभियंताओं, मुथ्य अभियंताओं ने अफनी काली कमाई से फैक्ट्रियां, फार्म हाऊसों, व्यवस्थाओं में पैसा लगा रखा है। जहां पर शासकीय वेतन के ये दैनिक वेतनभोगी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। अब पाठक अंदाज लगा सकते हैं कि किन स्वार्थों के चलते इन्हें 40 वर्ष से ज्यादा की सेवाओं के बाद भी नियमित तका दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता तो मात्र इसलिए कि इन भुखेरे शासकीय गिद्धों के हाथ से मुफ्त के काम करने जानवरों, जिन्हें राशन-पानी दिए बिना भी अपनी बीवियों की सेवा चाकरी में खाना बनाने, कपड़े धोने, घर की सफाई, बच्चों को नहलाने-धुलाने से लेकर अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों के सामने बड़े होने और नौकरों-चाकरों के गुरुर का प्रदर्शन किया जा सके। आईएएस वाइर्ल्स एसोसिएशन का ही फैसला है कि इन्हें नियमित करने की अपेक्षा मजदूरों का दर्जा देकर इन 50000 से ज्यादा कर्मियों और उनके तीन लाख से ज्यादा परिजनों को दो वक्त की रोटियां भी न मिलने दी जाएं।

दूसरी तरफ श्रम कानूनों में श्रमिकों की सुरक्षा और उसके रोजगार के स्थायिल के लिए स्पष्ट व्याख्या है कि जिस भी कर्मचारी ने 80 दिनों तक स्थाई रूप से कार्य कर लिया है, उन्हें स्थाई कर्मचारी माना जाए वरन् उनकी भविष्य निधि आदि का कटोत्रा कर उनके 60 वर्ष की आयु के पश्चात नियमित रूप से पेंशन आदि की व्यवस्था भी की जाए तो फैक्ट्री अधि. 1948 के अन्तर्गत, फैक्ट्री कार्य स्थली की श्रेणी में आते हों। जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी बिना शक्ति के उपयोग से व्यवसायिक कार्यों या 20 ज्यादा व्यक्ति बिना शक्ति के उपयोग के व्यक्त कार्य सम्पन्न कर रहे हों। हजारों प्रकरण श्रम न्यायालयों में लगाए गए, जिन्हें दिग्विजय की सरकार ने खारिज करवा दिया, ऐसे सैकड़ों प्रकरण उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक भी गए कुछ को जो सर्वोच्च न्यायालय गए थे राहत मिली और वे ही मात्र स्थाई किए गए। जबकि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर स्थाई किया जाना चाहिए था। पर वहां भी इन शूकरों की फौज आईएएस, आईएफएस लॉबी के धूर्तों ने अपने स्वार्थों के चलते उन्हें स्थाई नहीं होने दिया, क्योंकि सत्ता इनके बाप की जागीर थी और मुख्यमंत्री, मंत्री सब इनकी अप्रत्यक्ष रखेले हैं जो न केवल 5 वर्ष के मेहमान होते हैं। जिन्हें संबंधित मंत्रालय व विभाग की अ ब स भी नहीं आती। ये शूकरों की फौज इन मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्रियों, विधायकों को जितना जो बता देती हैं। जैसा कि वैसे ही सब इनके इशारों पर नाचने वाली कठपुलियां होते हैं। जैसा जो जहां बता देता है, उस पर ये मुख्यमंत्री और मंत्री दस्तखतों के दस्त कर देते हैं। बदले में शासकीय धन के टुकड़े इनकी तरफ अपना हिस्सा काट कर इन्हें दे देते हैं। इन भुखेरे मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को इतना धन देखकर और प्राप्त कर ये खुश होते हैं और अपनी मौज-मस्ती में डूब जाते हैं।

2003 के चुनाव में भाजपा की मुख्यमंत्री पद की दावेदार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सभी दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी करने की घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भारती ने पूरी काशिश की कि सभी दैनिक वेतम कर्मचारी स्थाई हो जाएं उस वक्त भी इन्हीं श्वानों आईएएस, अधिकारियों इंजीनियरों, डॉक्टरों और संचालकों व अन्य सैकड़ों मुफ्त खोर अधिकारियों के हाथों से वोटों के बिना दाना पानी की फौज हाथ से जाती दिखने लगी तो उन्होंने इसे लंबित कर रखा है कि आखिर ये भ्रष्टों की फौज सर्वोच्च न्यायालय तक को झूठे शपथ पत्र दे सकती है। पर घर की बीवियों के गुस्से का कोप भाजन कैसे बने उन्हीं के इशारे पर इन दैनिक वेतन कर्मियों को भाजपा ने अपने वादे से मुकरते हुए या धोखा देते हुए स्थाई करने की अपेक्षा मजदूर बना दिया।

वा. कर मुख्यालय इंदौर चलाया जाता है, मंत्री और पीएस के घर से

कदम-कदम जालसाजों और वसूलीबाजों का अड्डा है, भोपाल से नाकों तक

इंदौर। म.प्र. वाणिज्यिक कर मुख्यालय अब केवल शटिंग स्टेशन बन चुका है। सारा मुख्यालय का कार्य सचिव, प्रमुख सचिव और भ्रष्ट मंत्री राघवजी भोपाल से ही चलाते हैं। आयुक्त अमित राठौर यहां केवल शटिंग स्टेशन मास्टर की भूमिका का निर्वहन करने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठाया गया है। सारे निर्देश भोपाल से ही आते हैं और ये उन निर्देशों को केवल पालन करवाते हैं, यहां तक कि वृत्तो के वाणिज्यिक कर अधिकारियों से ऊपर के सभी अधिकारियों की सभाओं का, जिसमें सहा. आयुक्त, उपायुक्त आदि को भी भोपाल बुलाकर सचिव और प्रधान सचिव ही सभाओं में निर्देशित करते हैं। अर्थात हर कार्य में खुला लेन-देन सीधा भोपाल से ही मंत्री राघव जी और उनका खास एजेंट कम उपायुक्त एसडी निर्धारित करता है।

विभाग में इन वसूलीबाजों ने विभाग की मूल संरचना की जड़ें इस तरह हिला दी है कि न केवल बाबुओं अधिकारियों से लेकर व्यापारियों तक संदिग्ध कार्य पद्धति से परेशान हैं। इसके पीछे मूल में मोटा कमीशन टाटा से डकारना। कई गुना कीमत पर साफ्टवेयर बनाने का ठेका टाटा कंसलटेंसी को दिया गया। इसके साथ ही पुराने कम्प्यूटरों को कबाड़ बनाकर पटकने और 5 से 8 गुना ज्यादा कीमत पर टाटा कंसलटेंसी की सहायक कम्प्यूटर आपूर्ति करने वाली कम्पनी ट्यूलिप कम्प्यूटर जबलपुर से खरीदे गए, जिसमें भ्रष्टाचार की ओर 5 से 8 गुना ज्यादा बिलिंग के कम्प्यूटर आपूर्ति के बिलों के नं. और भुगतान

ए. इबे.के. नाकों पर नियुक्तियों की होती है, नीलामी, मंत्री, पीएस सब जालसाज वसूलीबाज, सू.अ. में मांगों कुछ तो या तो देंगे ही नहीं, देंगे कुछ और सीएम प्रशासन भी जालसाजियों में शामिल। वसूली के बाद भी स्व करनिर्धारण, आईटीआर

समय माया ने तीन वर्ष पहले ही छापे थे। साफ्टवेयर बनाने में भी टाटा कंसलटेंसी 4 वर्ष के बाद भी न तो ढंग से साफ्टवेयर बना पाई, जिससे व्यापारी और विभाग के अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी धीमी गति और बार-बार उलझने के कारण परेशान होते हैं। पर वित्त मंत्री और प्र.स. को अपने मोटे कमीशन से मतलब हैं। उनकी बला से व्यापारी और विभाग दोनों ही परेशान हो या खुश रहें। जबकि साफ्टवेयर की परेशानी का कारण सब ही जानते हैं कि केवल कमीश खोरी है, जबकि सी डेक द्वारा जो न केवल शासकीय उपक्रम था वरन् उसका बनाया साफ्टवेयर पर न केवल सफल था और बनाने में मात्र रुपए 25 लाख का ही खर्च आया था, जबकि उसके गुना ज्यादा पैसा साधन और स्टाफ के अनेकों युवा विभागीय इसकी परेशानियां दूर करने के लिए जाते गए जो रुपए 3 करोड़ की कीमत से 50 गुना ज्यादा थे। इन सब परेशानियों के चलते भी टाटा कंसलटेंसी को न तो समाप्त किया जा रहा है। साथ ही 10 गुना ज्यादा कीमतों में खरीदे गए कम्प्यूटर्स पर भी कमीशन डकारने के कारण न तो कोई विभागीय जांच की जा रही है, न हराम खोरों पर लोकायुक्त की जांच की कार्यवाही के लिए शिकायत की गई है। जबकि साफ्टवेयर की धीमी गति से हजारों घंटे मानवश्रम की विभाग और व्यापारियों करदाताओं की बर्बादी भी झेलना पड़ रही है, जिससे करोड़ों रुपए की जनहानि भी हो रही है। ऊपर से बाबुओं के स्टाफ की कमी भी भारी समस्या है। फिर यह समस्या चौगुनी हो जाती है। जब कार्यशीलकर्मियों को पूरे प्रदेशभर में जिलाधीश कार्यालयों में बुलाकर कभी मतदाता पहचान पत्र तो कभी मंडी चुनाव आदि के लिए बुला लिया जाता है। फिर महीनों तक उन कर्मियोंको मिलने वाला मानदेय जिलाधीश कार्यालय महीनों बाद तक पूरा भुगतान नहीं करता उसमें भी जिलाधीश, उपजिलाधीश व अन्य अधिकारी बंदरबांट कर डकार जाते हैं।

जहां तक टाटा के साफ्टवेयर का सवाल है उस हरामखोर ने पूरे म.प्र. के हर विभाग में मोटा कमीशन बांटकर कोषालयों जिला पंचायतों से लेकर लोक निर्माण आदि सभी विभागों में ऐसे ही आधे-अधूरे साफ्टवेयर्स देकर अरबों रुपए की कमाई कम्प्यूटर्स आपूर्ति में भी की है। स्वाभाविक है कि करोड़ों का कमीशन भी बांटा।

मप्र की सत्ता में बैठे भाजपाई भी दूसरी पारी में पूर्व के कां. मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह और स्व. अर्जुनसिंह की कार्य पद्धति को अपना कर कमाई में जुटे हैं। इसलिए अब वित्त मंत्री राघवजी ने भी अब हर कमाई के पद पर नियुक्ति के लिए बोली लगाई जाती है, जो भ्रष्ट जितना काला धन दे सकता है, उसे अपनी कमाई वाले पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। अर्थात भ्रष्टों और जालसाजों द्वारा की गई वसूली से धन बांटने और अच्छे कमाई वाले पद पर बैठा कर निवेशित धन से कई गुना ज्यादा कमाई करने के अनुसार एंटी एवेजन ब्यूरो बी में उपायुक्त भदौरिया को रुपए 35 लाख मंत्री को और रुपए 15 लाख उपायुक्त रिघारिया को देकर प्राप्त किया है। वहीं हाल ही में पदस्थ महाभ्रष्ट उपायुक्त सोनवलकर जिसने धार, सागर, इंदौर में वा. क्र. अ. और सहा. आयुक्त रहते भारी भ्रष्टाचार सलाहकारों के साथ मिलकर किया। अब उपायुक्त एंटी एवेजन अ में पदस्थ कर दिया गया है। आते ही साथ अपने द्वारा दिए गए मंत्रीजी को रुपए 50 और रिझारिया को दिए रुपए 25 लाख की वसूली के चाय व्यापारियों से रुपए 25 लाख का सौदा कर छोड़ दिया गया। थोड़ासा कर जमा करवाकर, उपायुक्त आरएस श्रीवास्तव से रुपए 10 लाख मंत्रीजी रुपए 5 लाख जबलपुर में पदस्थ उपायुक्त एसके जोशी रुपए 20 लाख और रुपए 10 लाख ग्वालियर में, सतना में उपायुक्त की नियुक्ति में उपायुक्त एस कुमार से रुपए 20 लाख व 10 लाख वसूली की गई। यही हाल 30 नाकों पर बैठाए गए वा.क.अ. व सहा. वा.क.अ. से रुपए 2 से 3 लाख नाकों की कमाई और ट्रकों की आवक के आधार पर वसूली कर नियुक्तियां दी गई। इस कमाई की सीडी भी भोपाल पहुंच गई है, जो इस समाचार की सत्यता सिद्ध करती है।

इसे कर निरोधक इकाई का गठन ही इसलिए किया गया था ताकि ये कर चोरों से ऊपरके ऊपर पैसा लेकर अपना हिस्सा रखकर बाकी हिस्सा ऊपर मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव तक पहुंचाते रहे और अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए 10-20 प्रतिशत कर भी चोरों से जमा करवाकर खुली लूट-पाट कर सकें। यही कारण है कि अधिकांश व्यापारियों को 100 प्रतिशत स्वकर निर्धारण की छूट दी गई। जन छूट नहीं थी तब भी व्यापारी, व्यवसायी 30 से 40 प्रतिशत कर जमा करवाया। अब स्वकर निर्धारित की सुविधा दे दी गई है तो अब 10 से 20 प्रतिशत ही कर शासन को मिल रहा है। अब जब छूट को 2-3 वर्ष बीत चुके हैं।

आयुक्त को चाहिए कि 75 प्रतिशत व्यापारियों की आकास्मिक जांच कराई जाए तो मालूम पड़ेगा कि सभी कर चोर हैं। जहां 4 में से 3 व्यापारियों की जांच कर दंड रोपित किया जाएगा। तब ये कर वसूली शासकीय स्तर 20 से 25 प्रतिशत पर आएगी। वैसे तो तत्काल प्रभाव से स्वकर निर्धारण पद्धति को बंद कर सभी अधिकारियों और निरीक्षकों को न केवल ट्रक पकड़ने वरन् व्यवसायिक परिसर में प्रवेशकर खाता बहियों की जांच से लेकर कम बिलों और स्टाफ तक की जांच का अधिकार दिया जाना चाहिए। चाहे फिर वह ट्रांसपोर्टर हो, उत्पादनकर्ता या विक्रेता हो, क्योंकि एंटी एवेजन की 8 इकाईयों के मात्र कर्मचारी अधिकारी न तो प्रदेश की सड़कों पर दौड़ते और माल ढोते 5 लाख से ज्यादा ट्रकों और बसों को पकड़कर जांच ने और टेक्स चोरी को पकड़ सकते हैं। न प्रदेश 25 लाख से ज्यादा व्यापारियों पर 100 वर्ष में भी छापे की कार्यवाही पूरी कर सकते हैं। फिर कोई भी चोर चोरी करते समय क्यों कोई चिल्ला कर बताएगा।फिर शासन को कर वसूली अधिकतम हो इससे मतलब होना चाहिए। भ्रष्टाचार फिर कौन नहीं कर रहा। क्या स्वयं मंत्री, मुख्य सचिव प्रधान सचिव, सचिव पद और शक्तियों के अनुसार वसूली कर रहे हैं तो फिर बाबुओं निरीक्षकों से ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जबकि काम तो सारा बाबुओं से ही करवाया जाता है, फिर सारा काम कम्प्यूटर्स से होने के बावजूद भले ही बाबुओं की कमाई समाप्त कर दी गई हो परन्तु अधिकारियों को तो बिना भ्रष्टाचार की कमाई के जीना मुश्किल हो जाए। युवा अधिकारियों का जोड़ दिया जाए तो पुराने अधिकारियों के बच्चों की फीस भी वेतन से नहीं भरी जा सकती। बेशक कम्प्यूटर्स इजेशन और स्वकर निर्धारण से न तो यथार्थ में विभाग को और न ही कर कर्मियों को तो लाभ हो ही नहीं रहा।

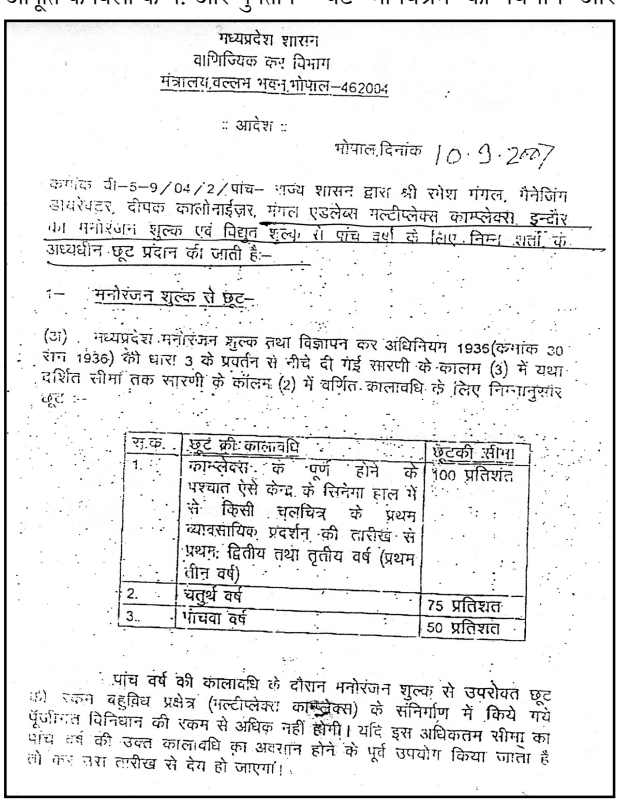

(शेष पेज 7 पर)

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल,दिनांक 10.9.2007

क्रमांक बी-5-9/04/2/पांच- राज्य शासन द्वारा श्री रमेश मंगल, मैनेजिंग डायरेक्टर, दीपक कालोनाईज़र, मंगल एडलेब्स मल्टीप्लेक्स काम्प्लेक्स, इन्दौर को मनोरंजन शुल्क एवं विद्युत शुल्क से पांच वर्ष के लिए निम्न शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान की जाती है:-

1- मनोरंजन शुल्क से छूट-

(अ) मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम 1936(क्रमांक 30 सन 1936) की धारा 3 के प्रवर्तन से नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में यथा दर्शित सीमा तक सारणी के कॉलम (2) में वर्णित कालावधि के लिए निम्नानुसार छूट :-

स.क.	छूट की कालावधि	छूटकी सीमा
1.	काम्प्लेक्स के पूर्ण होने के पश्चात ऐसे केन्द्र के सिनेमा हाल में से किसी चलचित्र के प्रथम व्यावसायिक प्रदर्शन की तारीख से प्रथम: द्वितीय तथा तृतीय वर्ष (प्रथम तीन वर्ष)	100 प्रतिशत
2.	चतुर्थ वर्ष	75 प्रतिशत
3.	पांचवा वर्ष	50 प्रतिशत

पांच वर्ष की कालावधि के दौरान मनोरंजन शुल्क से उपरोक्त छूट की रकम बहुविध प्रक्षेत्र (मल्टीप्लेक्स काम्प्लेक्स) के संनिर्माण में किये गये पूंजीगत विनिधान की रकम से अधिक नहीं होगी। यदि इस अधिकतम सीमा का पांच वर्ष की उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व उपयोग किया जाता है तो कर उस तारीख से देय हो जाएगा।

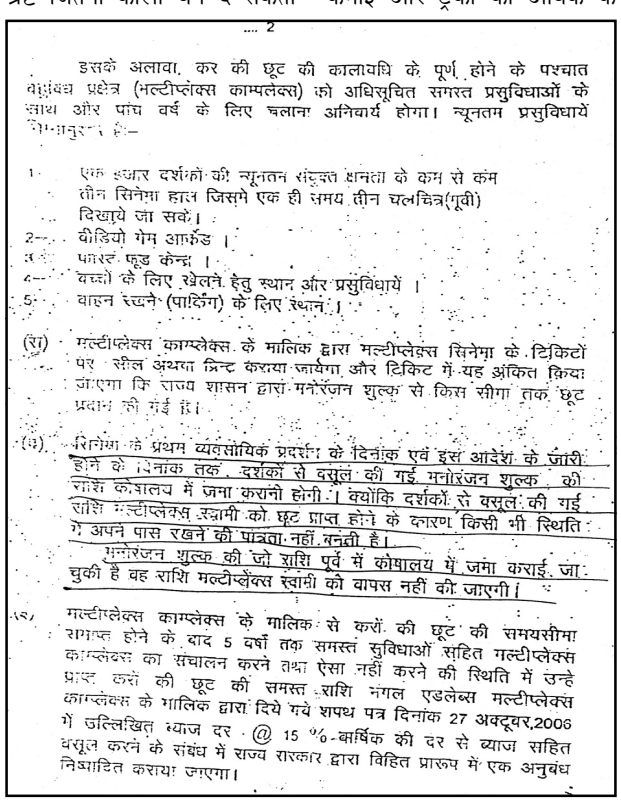

.... 2

इसके अलावा, कर की छूट की कालावधि के पूर्ण होने के पश्चात बहुविध प्रक्षेत्र (मल्टीप्लेक्स काम्पलेक्स) को अधिसूचित समस्त प्रसुविधाओं के साथ और पांच वर्ष के लिए चलाना अनिवार्य होगा। न्यूनतम प्रसुविधायें निम्नानुसार है:-

1- एक हजार दर्शकों की न्यूनतम संयुक्त क्षमता के कम से कम तीन सिनेमा हाल जिसमे एक ही समय तीन चलचित्र(मूवी) दिखाये जा सकें।
2- वीडियो गेम आर्केड ।
3- फास्ट फूड केन्द्र ।
4- बच्चों के लिए खेलने हेतु स्थान और प्रसुविधायें ।
5- वाहन रखने (पार्किंग) के लिए स्थान ।

(ख) मल्टीप्लेक्स काम्प्लेक्स के मालिक द्वारा मल्टीप्लेक्स सिनेमा के टिकिटों पर सील अथवा प्रिन्ट कराया जायेगा और टिकिट में यह अंकित किया जाएगा कि राज्य शासन द्वारा मनोरंजन शुल्क से किस सीमा तक छूट प्रदान की गई है।

(ग) सिनेमा के प्रथम व्यवसायिक प्रदर्शन के दिनांक एवं इस आदेश के जारी होने के दिनांक तक, दर्शकों से वसूल की गई मनोरंजन शुल्क की राशि कोषालय में जमा करानी होगी। क्योंकि दर्शकों से वसूल की गई राशि मल्टीप्लेक्स स्वामी को छूट प्राप्त होने के कारण किसी भी स्थिति में अपने पास रखने की पात्रता नहीं बनती है।
मनोरंजन शुल्क की जो राशि पूर्व में कोषालय में जमा कराई जा चुकी है वह राशि मल्टीप्लेक्स स्वामी को वापस नहीं की जाएगी।

(घ) मल्टीप्लेक्स काम्प्लेक्स के मालिक से करों की छूट की समयसीमा समाप्त होने के बाद 5 वर्षो तक समस्त सुविधाओं सहित मल्टीप्लेक्स काम्प्लेक्स का संचालन करने तथा ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हे प्राप्त करों की छूट की समस्त राशि मंगल एडलेब्स मल्टीप्लेक्स काम्प्लेक्स के मालिक द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 27 अक्टूबर,2006 में उल्लिखित ब्याज दर @ 15 %-वार्षिक की दर से ब्याज सहित वसूल करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक अनुबंध निष्पादित कराया जाएगा।

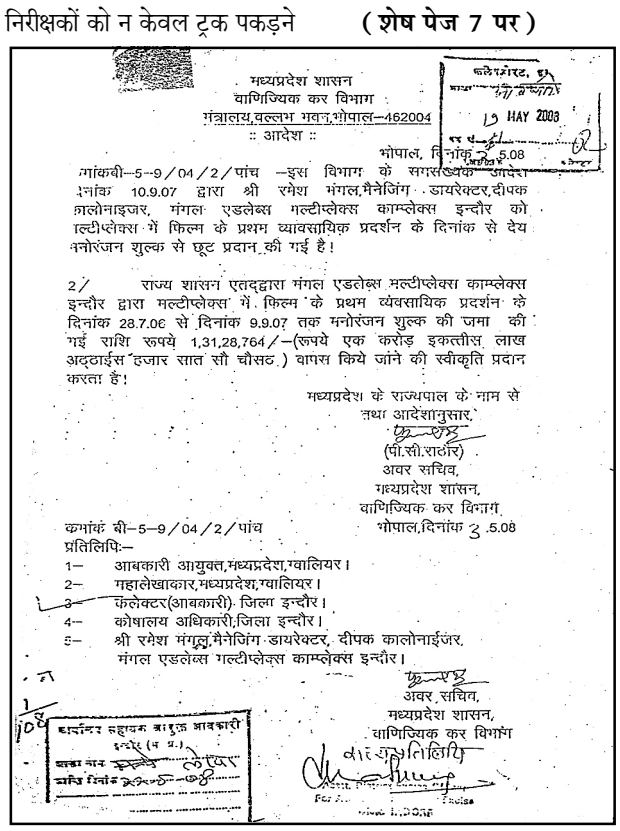

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल-462004
:: आदेश ::

13 MAY 2008

भोपाल, दिनांक 3.5.08

क्रमांकबी-5-9/04/2/पांच -इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.9.07 द्वारा श्री रमेश मंगल,मैनेजिंग डायरेक्टर,दीपक कालोनाइजर, मंगल एडलेब्स मल्टीप्लेक्स काम्प्लेक्स इन्दौर को मल्टीप्लेक्स में फिल्म के प्रथम व्यावसायिक प्रदर्शन के दिनांक से देय मनोरंजन शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

2/ राज्य शासन एतद्द्वारा मंगल एडलेब्स मल्टीप्लेक्स काम्प्लेक्स इन्दौर द्वारा मल्टीप्लेक्स में फिल्म के प्रथम व्यंवसायिक प्रदर्शन के दिनांक 28.7.06 से दिनांक 9.9.07 तक मनोरंजन शुल्क की जमा की गई राशि रूपये 1,31,28,764/-(रूपये एक करोड़ इकत्तीस लाख अट्ठाईस हजार सात सौ चौसठ) वापस किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(पी.सी.राठौर)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

क्रमांक बी-5-9/04/2/पांच
भोपाल,दिनांक 3.5.08

प्रतिलिपि:-
1- आबकारी आयुक्त,मध्यप्रदेश,ग्वालियर।
2- महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर।
3- कलेक्टर(आबकारी) जिला इन्दौर।
4- कोषालय अधिकारी,जिला इन्दौर।
5- श्री रमेश मंगल,मैनेजिंग डायरेक्टर, दीपक कालोनाईजर, मंगल एडलेब्स मल्टीप्लेक्स काम्प्लेक्स इन्दौर।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

मप्र शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट है कि दर्शकों से वसूला गया मनोरंजन कर लौटाया नहीं जाएगी, जबकि अंतिम आदेश में मंगल एडलेब्स को मनोरंजन कर लौटाया गया।

साप्ताहिक समय माया

सीएजी की टीम 2 से 5% छोटी कमियां ही पकड़ती है

अंकेक्षक-कागजीश्वान हैं, 99 प्रतिशत मामलों में लेनदेन

1500/- रु. से 3000/- रु. की रायल्टी मिल सकती थी कोयले में, 295/- रु. टन आंकी

भारत में महानियंत्रक, अंकेक्षक एवं लेखाकार जिसे कंट्रोलर ऑडीटर नजरल ऑफ इंडिया या सीएजी कहा जाता है। यथार्थ में करप्ट ऑडीटर्स गैंग होती है जो कि 99 प्रतिशत भ्रष्टाचार के प्रकरणों में लेन-देन कर बड़े-बड़े भ्रष्टाचार छोड़ कर कीड़े-मकोड़े मारकर केवल अंकेक्षण की खाना पूर्ति पिछले 65 प्रतिशत वर्षों से करती आ रही है। इसी सीएजी के पूरे भारत के हर राज्य में इनका कार्यालय है जो पूरे प्रदेश के केन्द्रीय और राज्यों के सभी विभागों का पूरे वर्ष भर अंकेक्षणकार्य करते हैं। यथार्थ में इस गिरोह के 99 प्रतिशत अंकेक्षण जहां और जिस विभाग का अंकेक्षण करने जाते हैं। इस विभाग के मुख्यालय को पहले ही अपनी यात्रा का विवरण भेज देते हैं। ताकि उनके पहुंचने से पहले ही सब चुस्त-दुरुस्त किया जा सके। दूसरा अधिकारी और कर्मचारी पूरे गिरोह के खाने-पीने रहने, सुरासुंदरी के योग-भोग से लेकर सेटिंग करनेस दान-दक्षिणा की व्यवस्था, घोटालों और भ्रष्टाचार के हिसाब से तैयार करने रखें। छोटे कार्यालयों में 5 व्यक्तियों का ये समूह अंकेक्षण के नाम अधिकांश दस्तावेजों की कागजी जांच की रस्म अदायगी करते हुए कानून दस्तावेजी प्रश्नावली तैयार करता है। यह प्रश्नावली दो प्रकार की बनाई जाती है। जिसमें बड़े वास्तविक जालसाजियों और भ्रष्टाचार की कहानी एक प्रश्नावली में और दूसरी प्रश्नावली में कानून ऐसा हेरा-फेरी जिस में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को आसानी से बचाया जा सके। प्रथम प्रश्नावली में शाम को 5 बजे के बाद संबंधित अधिकारियों के साथ खुली सौदेबाजी की जाती है। सौदा पट गया तो उससे उन कानूनी बड़ी जालसाजियों के दस्तावेजों को कानून दृष्टिकोण से ऐसा बना दिया जाता है ताकि भविष्य में अधिकारी और कर्मचारियों के फंसने की संभावना नगण्य हो जाती है। वैसे यह सौदेबाजी 1-2 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक हो सकती है। दूसरी सूची में छोटी-मोटी कमियां, कानूनों का उल्लंघन आदि की कहानी होती है, जिसकी जानकारी अपने वरिष्ठ कार्यालय को ये अंकेक्षण समूह भेजता है।

यही कहानी, कस्बों और तहसीलों के कार्यालयों से चलकर प्रधानमंत्री स्तर के कार्यालयों की भी होती है। यह बेशक एक आत्याधिक महत्वपूर्ण संस्था है, परन्तु इस संस्था के पास अत्याधिक सीमित अधिकारी है। सारा काम केवल कागजों तक ही सीमित होता है। जबकि 99 प्रतिशत जालसाजियां कार्य क्षेत्र में ही की जाती है। जैसे लोक निर्माण, लोक स्वा. यांत्रिकीय, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, ग्रामीण यांत्रिकीय विकास, प्राधिकरणों, नगर निगम, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा कृषि, उद्यानिकी, जिला पंचायत आदि अधिकांश विभाग शासकीय धन का उपयोग करते हैं। यह धन का सारा दुरुपयोग, सदुपयोग उपयोग ये सभी क्षेत्रों में करते हैं। परन्तु कागजों में तो वे सभी उसे ढंग से नियमों और कानूनों के हिसाब से ही खर्च करना दिखाते हैं। जबकि अधिकांश विभाग 25 से 100 प्रतिशत तक सारा झूठ कागजी कार्यवाही कर धन हजम कर जाते हैं। सीएजी ही अर्थात करार ऑडिट जनरल की टीमें इन्हें पकड़ ही नहीं पाती है। क्योंकि उन्हें फील्ड में जाकर वास्तविकता में जांचने परखने की न तो इजाजत होती है, न ही ऐसा इन्हें कोई प्रशिक्षण दिया जाता है। न ही इनके पास कोई तकनीक ज्ञान होता है।

यह इस राष्ट्र का दुर्भाग्य ही है कि आजादी के 65 वर्ष बाद भी हमारे तकनीकी अंकेक्षण, परीक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। प्रदेश स्तरों पर एक तकनीकी परीक्षक का बहुत छोटा सा विभाग है जिसे मुख्य तकनीकी परीक्षण कहा जाता है। परन्तु यह इतना छोटा सा है कि हजारों शिकायतें पहुंचने के बाद भी 1 प्रतिशत शिकायतों पर ही ध्यान दे पाता है। जबकि मुख्य सर्तकता परीक्षक का यह कार्यालय हर जिले में कम से कम 50 सहायक इंजीनियरों, 5 कार्यपालन अभियंताओं के साथ होना चाहिए जो न केवल सभी प्रकार के लोनिवि जल संसाधन, लोक स्वा. यां., नगर निगमों पालिकाओं, ग्रामीण यांत्रिकी सड़क विकास प्राधि. मप्र सड़क विकास निगम म.प्र. वि.मं. उसकी कम्पनियों जहां तकनीकी कार्य किए जाते हैं। उनका हर प्रकार के कार्यों की गुणवत्ता और बेहतर तकनीकी के मापदंडों को स्थापित करते हुए खर्च किए गए धन का अंकेक्षण करें, जैसा कि यूरोपीय राष्ट्रों में किया जाता है। यह संस्था निजी संस्थानों द्वारा निर्मित छोटी से छोटी मशीनों जो किसी भी क्षेत्र में काम करती हो। उनके उत्पादनों की श्रेष्ठता आदि का कार्य भी यही तकनीकी अंकेक्षण प्राधिकरण या अन्य किसी शासकीय समूह के रूप में कार्य करने की व्यवस्था की जाना चाहिए।

वर्तमान राष्ट्रीय सरकारी संस्था कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मात्र कागजों पर मुद्रित या लिखित शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा किए, करवाए गए कार्यों का शाब्दिक वितरण देखकर उचित अनुचित पर टिप्पणी करते हैं। कोयला खदान नीलामी घोटालों में भी करप्ट ऑडिटर जनरल के अधिकारियों और कर्मचारियों जो कोयला सरकार ने 50-80 रुपए टन के हिसाब अपनो-अपनो को बांट कर मोटा कमीशन उकारा उसका इस सीएजी की टीम ने वह आंकलन रुपए 295 प्रति टन के हिसाब से किया जबकि वास्तविक बाजार मूल रुपए 3000 से 5000 प्रति टन है। जिसे रुपए 1500 प्रति टन की रायल्टी देने के लिए बड़ी-बड़ी कम्पनियां तैयार थी पर उसे कोल इंडिया वेस्टर्न कोल फील्ड, सदक्षर्ने कोल फील्ड जैसी कम्पनियों को न देकर अपने खास-खास लोगों को रुपए 30 से लेकर 80 प्रति टन की रायल्टी में ही दे दिया गया अर्थात 50 गुना कम में।

सीएजी के आंकलन से रुपए 295 प्रतिटन के हिसाब से यदि रुपए 1 लाख 70 हजार करोड़ की रायल्टी उससे 5 गुना ज्यादा अर्थात रुपए 8 लाख 50 हजार करोड़ रुपए सरकार को रुपए 1500 प्रति टन की रायल्टी से मिल सकता था। सन दी लेखपाल या चार्टर्ड एकाउंटेंट के पाठ्यक्रम में यह स्पष्ट लिथा है कि अंकेक्षक केवल कागजी चौकीदारी श्वान है, न कि काटने वाला। अर्थात अंकेक्षकों की सीमा है कि वह केवल कागजी हेराफेरी की ही जांच परख कर सकता है। जबकि वास्तविकता में उसका वास्तविक क्षेत्रीय स्तर पर क्या काला-पीला किया गया, उसकी जांच परख का न तो कोई अधिकार है और न ही भारत में सीएजी की तरफ की कोई एजेंसी जो क्षेत्रीय स्तर पर जाकर उसके तकनीकी पहलुओं की सत्यता के बतला सके। यही कारण है कि क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं के धन 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हजम कर लेने के बाद भी यर्थाथ में भ्रष्टों को नहीं पकड़ा जा सकता। यही कारण है कि जिलों में जिलाधीशों से लेकर राज्य सरकार के हर जिले में चल रहे 90 से 100 विभागों के अधिकारियों से लेकर चपरासी तक सभी जिसको जहां मौका मिलता है, लूट खसोट होने के बाद भी 99.9 प्रतिशत मामलों में कहीं कोई कार्यवाही नहीं होती और सारा खेल कागजों पर ही उन्नति के आंकड़े दिखाकर जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटकर हजम कर लिया जाता है। सीएजी नाम की संस्था कहीं भी कुछ भी खास नहीं कर पाती।

राराप्रा के भ्रष्ट, ठेकेदारों के साथ सड़कों पर कर

मप्र के रा.रा. को बर्बाद किया अ
स्टाफ और मच रहा मौत क

भूमि अधिग्रहण में पीड़ी और एसडीएम कर रहे करोड़

भारत की सड़कों पर सत्ता में बैठे धूर्त, मक्कार श्वानों की फौज ने नोचने के लिए सड़क सुधार और विकास के नाम पर चारों तरफ पूरे राष्ट्र की 1 लाख किमी से ज्यादा सड़कों पर बीओटी (बनाओ चलाओ, दे जाओ) के ठेके केन्द्र ने राज्यों ने अपने बनाए गए प्राधिकरणों और नियमों के माध्यम से देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली।

केन्द्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए जिस राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया, उसमें प्रतिनियुक्ति पर चुन-चुन कर ऐसे भ्रष्ट, निक्कमों को बैठाया गया, जिन्हें सड़क निर्माणकार्यों का अनुभव नहीं था। दूसरी ओर यहां बैठाए गए इंजीनियर्स, परियोजना संचालकों को पेंच सुधार कार्य क अनुभव नहीं तो अरबों रुपए की सड़क बनवाने चले तो स्वाभाविक है कि वो ठेकेदार की कठपुतली बन नाचते रहेंगे। वैसे भी इंजीनियर और ठेकेदार का गठजोड़ दसियों सला पुराना चला आ रहा है। देवास-गुना रा.रा. क्र. 3 पर देवास से लेकर शाजापुर गुना मार्ग को बनाए हुए 4 माह भी नहीं बीते थे कि पूरा मार्ग गड्ढों और धूल का गुबार बन कर रह गया।

महाभ्रष्ट इंजीनियर सिंह जो कि म.प्र. जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में सलंग्न था, जिसे नहरें तालाब और बांध बनाने का अनुभव था। सड़कें बनाने और लूटमार करने प्रतिनियुक्ति पर पहुंच गए। क्या डामर, गिट्टी, चूरी का अनुभव था कि किस मिश्रण पर सड़क चल सकेगी। फिर दोनों ओर की पट्टियां पांच-पांच की भरने की तो दूर दोनों तरफ 5-5 का पता ही नहीं है तो भराव कैसे किया जा सकेगा। हरामखोरों से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगो तो उल्टे-सीधे जवाब, भारी-भरकम शुक्ल, इसके बाद भी आधी अधूरी जानकारी दी जाती है।

इंदौर से बैठा परि. सं. शैलेन्द्रसिंह उनका भी बाप है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इंदौर देवास की सड़के जिन पर दक्षिण के भ्रष्ट शूकर जो अपने भ्रष्टाचार जालसाजियों के लिए कुख्यात हैं। रेड्डी बंधुओं की गायत्री कंस्ट्रक्शन काम कर रही है। वसूली तो ये हरामखोर काम शुरू करने के साथ ही शुरू कर दी थी। पर सन् 2010 से वसूली करने के बाद भी इंदौर-देवास-राऊ बासपास सैकड़ों की मौत के बाद हजारों के हाथ पैर टूटने के बाद भी सड़क अगले 5 वर्ष में भी पूरी होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं। दूसरी ओर इस जालसाज परि. संचा. शैलेन्द्रसिंह ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी इंदौर व देवास के उप और सहा. जिलाधीश स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण में भी कर के करोड़ों रुपए हजम कर लिए। तरीका वही पुराना था, जहां बबूल का पेड़ था, शीशम की कीमत भुगतान करवाई गई। जो जमीन सूखी थी सिंचित दिखाई गई। कुएं आदि दिखाकर 2 पेड़ के स्थान पर बीस पेड़ों का भुगतान हुआ, जिन किसानों या भू माफियाओं से लेनदेन नहीं हुआ उनके 20 पेड़ों का भुगतान भी दे पेड़ों का दिया गया।

यहां तक कि रा.रा.प्रा. के इंदौर कार्यालय को भी ठेकेदार गायत्री कंस्ट्रक्शन के कार्यालय के परिसर में ही खोला गया ताकि उस ठेकेदार के इशारे पर ही कार्य सम्पन्न किया जाता रहे। बेशक रेड्डी बंधुओं ने देवास-इंदौर-राऊ बायपास का ठेका कम से कम रुपए 200 करोड़ की रिश्वत खिलाकर लिया होगा, जिसमें बिना काम शुरू किए ही हमारखोरों को वसूली का अधिकार मिल गया। इस मामले में म.प्र. सरकार को लोनिवि म.प्र. सड़क विकास निगम की तरफ से इस अनुबंध को रद्द करने या पुनःनिरीक्षण कर काम पूरा होने के बाद ही वसूली की जाना चाहिए। जबकि वर्तमान अनुबंध के अनुसार तो ठेकेदार यथार्थ में 5 वर्ष बाद भी कार्य पूरा नहीं करेगा, क्योंकि काम पूरा होने के बाद से ही उसकी अनुबंध ही अवधि प्रारंभ होगी। फिर उसे जिस तरह से जितना पैसा मांगलिया बायपास के ठेकों से मिल रहा है।

वह तो उस पैसे से ही कछुआ गति से कार्य कर रहा है। चूंकि परि. संचा. को महीना मिल रहा है, तो शूकर कैसे कुछ बोल सकता है। दूसरी ओर इंदौर-झाबुआ-दाहोद 192 किमी पर आईव्हीएसपीएल के निर्माण की मंथर गति ने लगभग 300 लोगों की जानलेती और हजारों घायल हो चुके हैं। पर इस धूर्त शैलेन्द्रसिंह ने मप्र की विधानसभा में उठाए गए प्रश्न का जवाब देना भी उचित नहीं समझा रा.रा. क्र. 3 इंदौर से खलघाट सेंधवा पर भी ढेरों तकनीकी खामियों और उचित रखरखाव के अभाव में सैकड़ों दुर्घटनाओं हर महीने हो रही है। पर वे शैलेन्द्र सिंह वहां से महीना खा रहा है। इसलिए इसकी बला से दुर्भाग्य यह है कि इन जालसाज ठेकेदारों पर और रा.रा. प्राधि. पर कोई भी दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित क्षतिपूर्ति और मुआवजे के लिए करोड़ों रुपए का मुकदमा उपभोक्ता न्यायालय तक में नहीं लगा रहा है, जबकि टोल का भुगतान हर वाहन चालक दे रहा है।

इंदौर बेतुल रा.रा.क्र. 53व इसमें भी इस श्वान शैलेन्द्र सिंह ठेकेदार पीडी गोयल के साथ मिलकर इन्हें दोनों तरफ मिली 30-30 फुट में लगे लाखों पेड़ मिले ठेकेदार और सिंह ने मिलकर उनकी बेरहमी से न केवल कटाई करवाई वह लकड़ी न तो वन विभाग में जमा की गई, न ही इसका हिसाब-किताब विभाग को किया गया। लाखों पेड़ों की लकड़ी बाले-बाले बेंचकर हजम कर ली गई। इसके साथ ही सड़क बनने के 6 माह के अंदर ही गड्ढों से भर गई, जिस पर चिगड़े भी ऐसे लगाए गए जो उबड़-खाबड़ हो गए। दोनों तरफ 5-5 की न तो पट्टियां भरी गई, न ही जहां पट्टियां नहीं थी भरकर सड़क के तल से मिलाया गया। न पुल पुलियाएं सुधारी गई 15 किमी घाट से वर्शन जैसे 20-25 वर्ष से ऊबड़-खाबड़ पुल भरा था। वैसे ही अभी भी है। यह पूरा 53-ए चार लेन बनाने की योजना दो लेन में सिमटा दी गई।

परन्तु सड़क भारतीय सड़क कांग्रेस के मापदंडों का कहीं भी वेरीकेड नहीं लगाए गए और जैसा कि समय माया ने लिखा था कि एनएचएआई में सारे अधिकारियों-कर्मचारियों अनुभयव्हीन व लूट की मानसिकता लिए हुए हैं। न सड़के बनवा पाएंगे और न रखरखाव और 2-5 वर्ष बाद वापस म.प्र. लोक निर्माण रा.राजमार्गों को जो म.प्र. की सीमा में है। हाल ही में 2342 किमी सड़केन पुनः म.प्र. को सौंप दी है। अभी जो 2367 किमी सड़के केन्द्र के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में है। धीरे-धीरे

रही वसूली

अनुभवहीन ा तांडव

ों की हेराफेरी

अधिकांश सड़के इन्हें पुनः म.प्र. शासन को ही सौंपनी पड़ेगी। पर जब तक इन निकम्मे भ्रष्ट ठेकेदारों और परियोजना संचालकों की अनुभव हीनता और लूट की मानसिकता ही 8-10 हजार लोगों की मौत का कारण बन जाएगा।

हाल ही में इंदौर के एसडीएम पर्यावरण के अन्तर्गत म.प्र. प्रदूषण फैलाओं मंडल के 20 वर्षों से अजगर की तरह चिपके जालसाज भ्रष्ट क्षेत्र अधिकारी ए.ए. मिश्रा और रा.रा.प्रा. के परि. संचा. सिंह ने मिलकर इंदौर में बनने वाले लगभग 50 किमी लंबे बायपास की जनसुनवाई मांगलिया के बाहर बायपास, मांगलिया-देवास के तिराहे पर एकदम एकांत में आयोजित की ताकि क्षेत्रीय जनता को मालूम न पड़े और जन सुनवाई की औपचारिकता भी पूरी हो जाए। इसी बीच श्री अजमेरा वहां से गुजरे और सरकारी गाड़ियां और तंबू लगा देखकर कैमरा चालू करके घुस गए।

तो कैमरा देखते ही सारे औपचारिक आयोजन के रंग में भंग हो गया। सभा समाप्ति की घोषणा कर दी गई और साक्षात्कार देने से मना कर दिया गया। इस जन सुनवाई की भनक जब मांगलियावासियों को लगी तो पीड़ितों ने इकट्ठे होना शुरू किया पर जब तक सभा समाप्त हो चुकी थी। दोनों धूर्त एसडीएम और पीडी जिन्होंने पहले भू अधिग्रहण में जालसाजियां की थी अब बायपास में भू अधिग्रहण में फिर वही जालसाजियां दोहराई जाएंगी और पीड़ितों की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएगी और ये शूकर पुनः भुगतानों में लूट-पाट करेंगे।

केन्द्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय को अपनी योजनाओं को पुनः समीक्षा करना चाहिए यदि नहीं संभल रहा है तो राज्य की एजेंसियों से कार्य क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार सम्पन्न करना चाहिए। साथ ही म.प्र. राज्य के साथ अन्य हिस्सों में बैठाए गए परि. संचालकों की जालसाजियों की जांच सीबीआई से करवाना चाहिए।

प्र.मं.का. विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार व साजिशों का अड्डा

पेज 1 का शेष

इसके विपरित उन दायित्वों के निर्वहन की अपेक्षा, यर्थात में उनके हितों के शोषण और उसके साथ कदम-कदम पर लूट खसोट जो हर दिन लाखों-करोड़ों में होती है। कर अपने हित संधान में जुटा हुआ है। इसके लिए तो झूठ, मक्कारी, जालसाजी करते हुए भी अपने आप की निहायत मासूम बना रहना चाहता है। जनता से हर दिन अकेले मोबाइल फोन सेवाओं में ही करोड़ों हजारों करोड़ की लूट कर ली जाती है। इसके विपरित संचार मंत्रालय ने न केवल 2जी, 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में लाखों करोड़ इसी दम पर लूटे और लुटाए। क्योंकि सभी मोबाइल कं. को जनता हर वर्ष लाखों करोड़ की लूट की पूरी छूट दे रखी है।

इस पर ट्राई भी सौंठ मारकर चुप हैं। साथ ही प्रति सेंकड और मिनिट की दरों में लूट, अनावश्यक रिंगटोन, कॉलर ट्यून व अन्य सेवाओं के नाम पर लूट की जा रही है। उसके विरुद्ध उसकी साइट पर शिकायत की कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। अंबानी की स्मार्ट, बेतार क्षेत्रीय संयोजन जिसे वायरलेस लोकल लूप कहा जाता है। बिरला की आइडिया, भारती की एयरटेल, टाटा की इंडिकॉम और डोकोमो आदि योजनाओं में अरबों रुपए के कमीशन की सत्यता महीनों पूर्व सामने आ चुकी है। पेट्रैलियम मंत्रालय की लूट में पूरे देश में अंबानी बंधुओं का वर्चस्व है। उसकी लूट के चलते पेट्रोल व रसायन मंत्री को हटाया जा चुका है। डीजल, पेट्रोल, गैस मिट्टी तेल में भी लाखों करोड़ का कमीशन का खेल का संचालन भी अंबानी प्रधानमंत्री कार्यालय से ही करता व करवाता है, ओमान से आयातीत गैस की कुल कीमत रुपए 1.80 पै. प्रति ली. होती है, जिसे मंत्रालय रुपए 14 प्रति ली. खरीदकर तेल कम्पनियों को बेंचता है। अब रुपए 1/40 प्रति ली. की गैस पर जो यदि 1 अरब करोड़ लीटर खर्च होती है। सालभर में तो लाख करोड़ की वसूली खरीदी में और फिर 14 ली. का सिलेंडर रुपए 450 में भी बेंचा तो रुपए 34 प्रति ली. जो बाजार में वाहनों के लिए रुपए 55 प्रति ली. में बेंची जा रही है। आम जनता समझे कि कौन सा अनुदान इटली से आ रहा है। मनमोहन के बचत खाते से दिया जा रहा है। जबकि केजी बेसिन-6 की गैस आदि कीमते और भी कम होती है जो 50-60 पै. प्र.लि. ही पड़ती है। ये मात्र दो शास. सेवाओं का हाल है। फिर किसानों से रुपए 14 प्रति ली. का गेहूं खरीद कर लाखों टन रुपए 30-40 प्रति ली. में खाड़ी देशों में बेंचा जाता है। वहां से राशन की दुकानों में आपूर्ति के लिए सड़ा खराब या स्तरहीन गेहूं अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया से रुपए 1-2 में आयात किया जाता है। केवल लाखों करोड़ के कमीशन के लिए वही हाल खाद्य तेलों, शक्कर से लेकर खेतों के लिए करोड़ों टन खाद्य के आयात में भी रुपए 2 प्रति ली. का खाद्य रुपए 20 से 50 में आयात किया जाता है। रक्षा सौदों में भी रु. 1 में खरीदे गए कबाड़ गोर्श की कीमत कांग्रेस सरकार रुपए 16,000 करोड़ में कर रही है। रूप से अभी जब राष्ट्र बलात्कार की आग में जल रहा था। हमारे प्रधानमंत्री रुपए 22,000 करोड़ की रक्षा सौदा पुतिन के साथ कर रहे थे।

समय माया ने पूर्व में भी लाखों करोड़ की योजना में लूट और साजिश के बारे में छापा ही था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना पुर्नजनन बालस्वास्थ्य सर्वशिक्षा अभियान में लाखों करोड़ रुपए बांटने के नाम यर्थाथ में या सुधार आयो. जनता बलांत वसूले गए करों को जनहितों के नाम पर बलात केन्द्रीय

मंत्रालय से नीचे ग्राम पंचायत तक सब ने धन हजम किया। यही हाल कृषि मंत्रालय में सभी प्रकार की फसलों के बीजों के साथ लाखों करोड़ डकार कर कृषि ने भारत की मूल पारंपरिक पौष्टिक बीजों को उनकी नस्ल सौप कर बदले में उनके बीटी, जीएम, हायाकोड के नाम पर उनके हजारों गुना महंगे बीज, दलहन, तिलहन, अनाज के साथ मसालों, सब्जियों, जड़ी-बुटियों तक में खेल किया गया। हजारों करोड़ रुपए हजम करके देशी हल्दी, बासमती चावल, शरबती गेहूं, नीम, करेले, परवल, जैसी हजारों सब्जियों, जड़ी-बूटियों मसालों, फलों के मूल प्रजाति की फसलों जो भारत की कृषि भूमि पर लाखों वर्षों से पैदा की जा रही थी, उनके पेटेंट कैसे यूरोपीयन कृषि, औषधियों आदि की कं. के पास पंजीकृच है। पर हमारे यहां कमीशन राक्षस श्रेष्ठ मनमोहन से लेकर हर मंत्री ने चुपचाप सब देखते हुए हो जाने दिया।

चटुकारों की सत्ताधीश फौज जो प्रधानमंत्री कार्यालय से संचालित होती है ने राष्ट्र की राष्ट्रीय राजमार्गों की 1 लाख किमी की सड़कों को गिरवी कर हर किमी पर भात्र 5 से 8 करोड़ प्रति किमी के कमीशन पर ठेकेदारों को सोचकर मात्र प्रतिदिन सड़कों पर मात्र 5 से 8 करोड़ वाहनों को मात्र रुपए 2 से 5 प्रति किमी की दर से लूटने के लिए छोड़ दिया। सारे नियम कानून बदल दिए गए। अब हिसाब लगाए कि मात्र 3 करोड़ वाहन औसतन 100 किमी इन सड़कों चलते हैं और औसतन 3 प्रति 3 किमी का भुगतान करते हैं। अर्थात रुपए 900 करोड़ की लूट प्रति दिन सड़कों पर बीओटी के ठेकेदार वसूल पर लूटते हैं। इससे दोगुना पैसा हर दिन डीजल, पैट्रोल पर 2 प्रतिशत की दर से सड़क सेस के नाम पर सरकार दो पहिया वाहन से लेकर 10 पहिया वाहन तक जो कुल 20 करोड़ होंगे पर वसूली है और औसतन 5 ली. पेट्रोल, डीजल गैस खपत करते रहे। कहा जा रहा है तो सारा केन्द्रीय सड़क निंधि का।

बिजली के मामले में भी इसी प्रधान मंत्री कार्यालय ने विश्व व्यापार संगठन के दबाव के चलते सारे देश के राज्य विद्युत मंजलों को भंग करके कम्पनियां बना दी। इन कम्पनियों को काम ही जनता को लूटना 20 पै. प्रति यूनिट की जल विद्युत को रुपए 5 से 15 प्रति यूनिट ताप विद्युत की 60-70 पै. युनिट की बिजली आदि सब को टाटा, अंबानी, बिरबा को सौंप कर जनता को रुपए 20-50 अरब की चोट पहुंचाई जा रही है। देश की 125 करोड़ जनता को। इससे पेट नहीं भरा तो इसी मनमोहन राक्षस ने विदेशों से सारे समय बाधित प्लांटों को खरीदकर देश में लगाने और परमाणु ईंधन खरीदने के सौदे कर डाले, पूरे देश की संसद में महीनों हंगामा मचा रहा पर कमीशन राक्षस ने कमीशन बांटकर सरकार बचा ली।

देश की 125 करोड़ जनता पर विदेशी दवा निर्माता कम्पनियों और उनकी जन सम्पर्क कम्पनी जिसे विश्व स्वा. संगठन के नाम से जाना जाता है। इसी मनमोहन सरकारी सत्ता से आते ही लाखों डकार कर इन 125 करोड़ जानवरों पर बिना किसी औपचारिक मानक तय किए ही औषधि परीक्षण की खुली छूट दे दी। यह कांड मात्र इंदौर से आनंद राय ने खोला जबकि देश के हर निजी व शासकीय चिकित्सालय में हर दिन करोड़ों मरीज के साथ खुलेआम किया जा रहा है। 50 प्रतिशत मौतें शिशुओं से लेकर युवाओं और बुजुर्गों की इसी औषधि परीक्षण से हो रही है। सूचना के अधिकार में जानकारियों से यह तथ्य स्पष्ट भी हो चुका है कि पूरे देश में औषधि परीक्षण का अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है।

ब्रैकिंग उद्योग में सीआरआर, ब्याज दरों, ऋणमाफी, निवेश के नाम पर भी अरबों रुपए का खेल एक झटके में ही हो जाता है। चांडाल चौकड़ी जिसमें प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री या कृषि मंत्री मिल कर करते रहते हैं। यहां हर योजना, हर कार्य, बिना हजारों करोड़ की वसूली बिना नहीं किया जाता। खेल मंत्रालय का हाल ओलंपिक खेलों में हुआ हजारों करोड़ का घोटाला सामने आ ही चुका है। खाद्य सुरक्षा और मानके अधि. 06 भी करोड़ों लोगों की बेरोजगार बनाकर जो बहुराष्ट्रीय कं. को पेकिंग में खाद्य सामग्री मिलावटी, स्तरहीन, घातक रसायनों युक्त बेंचने के षड्यंत्रों में भी एक मुस्त लाखों करोड़ कमाने के साथ ही हजारों करोड़ रुपए प्रति माह की आय राज्य और केन्द्र के के सत्ताधीशों को होगी। इसलिए उसे लागू करवाया गया अब कोई भी खाद्य तेल, मसाले, खाद्य पदार्थ न केवल शुद्ध तको होते ही नहीं वरन महंगे मिलावटी और घातक रसायन युक्त भी होते हैं जो न केवल पाचन शक्ति को खराब कर रहे हैं। वरन् बच्चों और युवाओं को गंभीर प्रोठा वस्था और वृद्धावस्था के रोग यथा ऊंच निम्न रक्तचाप, हृदयघात जैसी बीमारियां भी दे रहे हैं, जिसमें साफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, पेक्ट फूट सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हो रहे हैं। पर इन सत्ताधीश गिद्धों की चलती रहे कमीशन की दुकान बच्चा मरे या जवान।

ये हजारों करोड़ की लूट, केन्द्रीय 50 से ज्यादा मंत्रालयों में रेल, रक्षा, इस्पात, भारी उद्योग एखं सार्वजनिक उपक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मामलों, ऊर्जा विधि एवं न्याय, शहरी निकासी, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्गों, अप्रवासी भारतीय मामले, जल संसाधन, वन पर्यावरण मंत्रालय, कपड़ा, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूचना एवं प्रसारण, श्रम एवं रोजगार मानव संसाधन एवं विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं खदान, वाणिज्यि एवं उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन, पर्यटन खाद्य संस्करण उद्योग, खेल एवं युवा मामले, जहाज रानी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता जनजातिय मामले, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भू-विज्ञान, लोक शिकायत, पेंशन, कोयला संगरणीय व कार्यक्रम क्रियान्वयन, संस्थागत कार्य अल्पसंख्यक मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उपक्रम मंत्रालय महिला एवं बाल विकास आदि के मंत्रियों प्रधान सचिवों, सचिवों, पर और अधिकारियों आदि में लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार में भी प्रधानमंत्री कार्यालय की ही अहम भूमिका रहता है। 125 करोड़ जनता के साथ विश्व श्रेष्ठ जालसाजों के अड्डे प्रधानमंत्री कार्यालय में हर कदम जालसाजियां, लूट, घोटालेबाजी, जनहितों के साथ खुदा बलात्कार होता है।

जनता को खुश करने व सरकार बचाने का नाटक

पेज 1 का शेष

सरकार आसानी से चलाई जा रही थी देश के 125 करोड़ मूर्ख जनता को ये आसानी से हांक रहे थे, फिर इतने ही राष्ट्रभक्त और कानून के रखवाले हों तो जालसाजों उस अफजल गुरू को 8 वर्षों से क्यों मुर्ग मुस्लम और बिरयानी, अफगानी खिलाकर पाल रहे हो, क्योंकि ये संकर प्रजाति के कांग्रेसियों को डर है कि मुस्लिम वोट बैंक हाथ से न खिसक जाए। मुस्लिम नाराज न हो जाएं। दूसरी ओर यदि सच ही कसाब फांसी पर लटका दिया होता तो न केवल पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, काश्मीरी और बांग्लादेशी जिसे पाकिस्तानी पाल रहा है। केरल, आंध्रप्रदेश और देश में फैले और ऊपर शांत दिखने वाले इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य और संगठन क्या शांत रहते कदापि नहीं। फिर हाल ही में पाकिस्तानी विदेश मंत्री रहमान मलिक ने सारी बातें भारत में आकर भी अप्रत्यक्ष रूप से भाईचारे और दोस्ती करने की आड़ में भी बोली तो भारत के विरुद्ध ही, इतनी लंबी चर्चा के बाद भी अजमल कसाब का नाम कहीं नहीं मिला। यदि फांसी पर लटका ही दिया होता तो भारत ही नहीं आता और आता तो कहीं न कहीं गुस्से का इजहार अवश्क करता।

जहां तक कांग्रेसी जालसाजों का सवाल है तो ये तो जिंदा को भी सार्वजनिक रूप से किसी भी दुर्घटना में मारकर उसका भविष्य चौपट कर देते हैं। जैसे कि स्व. सुभाषचन्द्र बोस के साथ किया। आजादी के बाद नेहरू गांधी को लगा कि यदि सुभाषचन्द्र बोस की जीवित बताया गया तो सारी जनता उनको सत्ता में देखना चाहेगी, इसलिए उन्हें 1945 की हवाई दुर्घटना में मौत होना बताकर उन्हें इतिहास में दफन कर दिया गया, जबकि जहां उनकी हवाई दुर्घटना बताई गई थी, वहां कोई विमान दुर्घटना ग्रस्त ही नहीं हुआ था, जबकि नेताजी स्वामी श्रद्धानंद के रूप 1986 तक हैदराबाद में जीवित रहे थे, फिर देहरादून में इस व्यक्ति की मौत पर पूरा सैन्य सम्मान और सलामी के साथ अंत्येष्ठी की गई जो अनाधिकृत रूप से की गई। गूगल से जानकारी से प्राप्त की जा सकती है। अस्तुः यह सब कांग्रेस का चरित्र है, लालबहादुर शास्त्री का ताशकंद समझौते के बहाने रूस में बुलाकर दूध में विष देकर मारा गया, जबकि भोजन वो अपने हाथ से ही बनाकर खाते थे, उनकी मौत के बाद ही सत्ता स्व. इंदिरा गांधी ने संभाली थी, नेहरू गांधी खानदान के दामन पर ऐसे सैकड़ों दाग हैं अपराधों और जालसाजियों के।

भारत की जनता इस सरकारी कसाब की नौटंकी पर भले ही खुश होकर फटाके फोड़कर खुशी मना लें। हर सत्ताधीश चाहता है कि जनता यर्थाथ में भारी दहशत, परेशानी में जिये और उसे झूठी खुशियों से भृमित कर अपनी कमाई लूट, डकैतियों, देश को गिरवी रखने बैचने के कार्यों को सम्पन्न करते रहो। जनता सत्ताधीशों के हर छल, कपट, जालसाजियों को मात्र 0.5 प्रतिशत समझ पा रही है। फिर कांग्रेस का शगल है। देश की जनता को दहशत, भ्रमपूर्ण खुशियां, क्रिकेट मेच, किसी भी छोटी सी बात का बतंगड़ तिल का ताड़ और राड़ का पहाड़ खड़ा करके मीडिया में उछालकर जनता का ध्यान बंटाए रखना और अपनी जालसाजियों को अंजाम देना अरबों करोड़ का हेर-फेर करना।

साप्ताहिक समय माया

गैस में अनुदान के नाम फैला रहे आतंक

पेज 1 का शेष

जो हर वक्त पेट्रोल डीजल और गैस में अनुदान खत्म करने की बात कहकर जनता को भ्रमित करके सन् 2004 में पेट्रोल की कीमतें 34 रुपए थी वह सन् 2011 में ही रुपए 75 प्रति लीटर अर्थात दुगुनी कर दी गई, जबकि पेट्रोल में ही सबसे ज्यादा न केवल केन्द्र सरकार 32 प्रतिशत कस्टम और वरन् 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर, 2 प्रतिशत निधि, 2 प्रतिशत शेष अर्थात 38 प्रतिशत लूटती है। वहीं इतना ही राज्य सरकारें भी डीजल पेट्रोल और गैस पर टैक्स लगाकर लूटते हैं। इसके बाद भी अनुदान का रोना रोते हैं। फिर 76 प्रतिशत टैक्स वसूल कर, 10-20 प्रतिशत अनुदान दे भी दिया तो ये शूकरों की फौज किस पर अहसान दिखाती है। यह सच चूंकि मीडिया के दृष्ट और श्रण्य माध्यम न तो जानते हैं तो बगाएंगे क्या?

इस राष्ट्र की जनता का ये दुर्भाग्य है कि इस राष्ट्र का पूरा श्रण्य दृष्य और मुद्रित प्रसार माध्यमों में बैठे अधिकांश प्रसारकर्मी, पत्रकार 10वीं, 12वीं पास होते हैं। या नई युवा पीढ़ी पत्रकारिता को पाठ्यक्रम पूरा करके अपने आपको महान पत्रकार समझ बैठते हैं। दूसरी ओर अधिकांश टीवी चैनल्स और मुद्रित समाचार पत्र माध्यक्ष भी पूंजीपतियों और सत्ताधीशों की रखैल बन नाचने और वसूली का कार्य करते रहते हैं। उन्हें हर सरकारी दावों घोषणाओं, वक्तव्यों का बारिकी से हर दृष्टिकोण से जांच परख कर समाचार प्रसारित और मुद्रित करना चाहिए। पर जहां कमाई, कसाई बन कर किया जाना ही उद्देश्य हो तो और झूठ का कोई औचित्त नहीं।

हर बार जब सत्ताधीश अनुदान का विगुफा छोड़ कर कीमतें बढ़ाते हैं, तो क्यों नहीं कोई भी चैनल का पत्रकार पूछता कि ये अनुदान किस प्रधानमंत्री, इस देश की अघोषित राष्ट्र द्वारा सोनिया गांधी के खाते से आ रहा है। फिर पेट्रोल डीजल और गैस पर 38 प्रतिशत केन्द्र के और लगभग इतने ही राज्यों के भारी टैक्स वसूली क्यों कर रहे हैं। एक तरफ भारी भरकम टैक्स और फिर अनुदान का रोना आखिर क्यों? दोनोह एक साथ कैसे?

सत्यता इसके विपरित बहुत अलग हैं। इस राष्ट्र का पूरा पेट्रोलियम मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय पर यर्थाथ में कब्जा अंबानी बंधुओं की रिलायंस का है। जिसको फायदा पहुंचाने के लिए जनता को लूटा जाता है। आखिर सबसे बड़ा तथ्य कि केजीवेसिन 6 की जो आकूत गैस ओएनसी खोजी खोदी और निकासी थी तो रिलायंस के पास कैसे पहुंची और क्यों पहुंची। अरबों-करोड़ कमीशन डकार कर उसे बेंच दी गई। फिर जिस अनुबंध के तहत उसे गैस निकालने की इजाजत दी गई थी, वह उन शर्तों को स्वयं ने तो पूरा नहीं किया और उसे बाले-बाले ही ब्रिटीश पेट्रोलियम को क्यों बेचा गया? पर उस पर ये जालसाज गिद्धों की फौज मुंह में डही जमाए बैठी है। फिर विपक्ष भी न केवल बिखरा हुआ वरन् रिलायंस के हाथों बिका हुआ है, वह भी सरकार से जवान सवाल नहीं करता तो बिकी हुआ मानसिकता के कारण।

दूसरी ओर कांग्रेसी धुर्तों को अपना आतंक फैलाना और जनता को अपने सत्ताधीश होने का अहसास कराने और वोटों की राजनीति करने के नाम पर कब्र में पैर लटकाए बैठे धूर्त मनमोहन ने पहले 6 सिलेंडर देने, फिर अनुदान को बैंक खातों में अंतरण करने के जो शिगुफे छोड़े हैं। तो केवल अपना चुनावी मंच जमाने की रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल वैसे ही गरीबों का वोट छीनने और दो वक्त की रोटी के टुकड़े डाल कर उन्हें गुलाम कर उन्हें गुलाम बनाकर रखने के फूड सिक्युरिटी बिल ताकि बहुराष्ट्रीय कं. के फूटकर व्यवसाय जमाने में जनता विद्रोह न करे और इन सत्ताधीश हरामखोरों को हर महीने मोटा कमीशन मिलता रहे। दूसरी ओर इनका अपना वोट बैंक बना रहे। इस अनुदान बैंक खाते में जमा करने का शिगुफा छोड़ा गया है। पहले लोगों को गुलाम बनाने के लिए मुफ्त का अनुदान खाने के आदत डाली जाएगी ताकि वोट बैंक मजबूत हो, फिर भी अगर वोट नहीं मिले या मिल भी गए तो शापिंग माल्स में खाद्य वस्तुओं की कीमतें इतनी महंगी कर दी जाएंगी ताकि अनुदान और कमाई को वक्त की रोटी को भी पूरा नहीं पड़े। फिर अनुदान है जीतने के बाद बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अंधा बांटे रेवड़ी चीन्ह-चीन्ह आप-आप को लेय। की कहावत चरितार्थ करते हुए नेता और अधिकारीगण अपनो-अपनों को बांटकर कर जाएंगे, जिनको वास्तविक वास्तविकता में मिलना चाहिए मनरेगा की तरह मिलना चाहिए उन्हें या तो कभी मिलेगा ही नहीं या मिलेगा तो भी काम 50 घंटे का, दाम 10 घंटे का वहीं हाल इस गैस अनुदान का होगा।

इन सत्ताधीश धुर्तों की गैस सिलेंडर को 6 पर सीमित करने का सीधा असर जंगलों से जुड़ गया है। गैस और मिट्टी का तेल ने मिलने के कारण न केवल ग्रामीणों ने वरन् इंदौर जैसे म.प्र. की वाणिज्यिक व्यवसायिकता राजधानी में गरीबों ने पुनः पारंपरिक तौर तरीके के चुल्हे-लकड़ी से जलाना शुरू कर दिए हैं। हालात ये बन गए कि म.प्र. में जलाऊ लकड़ी बाहर से, अर्थात अड़ोसी-पड़ोसी राज्यों से आयात करनी पड़ रही है।

गैस की सुलभत्ता से जंगलों की कटाई 3 से 5 प्रतिशत की दर से हो रही थी उन जंगलों की चोरी-छिपे और प्रत्यक्ष में ये कटाई बंद कर पुनः 5 से 8 प्रतिशत पहुंचने लगी है। क्योंकि ईंधन खाना पकाने के लिए हर किसी को चाहिए है, यदि गैस और मिट्टी का तेल सुलबत्ता से नहीं मिलेगा तो लड़की जलाने के विकता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर लकड़ी के लिए जंगलों की कटाई के अतिरिक्त भी कोई विफल नहीं है तो कोयला भी भारी महंगा है।

हाल ही में जब गांवों की यात्रापर जाना पड़ा तो मालूम पड़ा सड़कों के किनारे बने हर चाय-पान भोजन आदि की दुकानों और ढाबों पर लकड़ी जलाई जा रही थी, पूछताछ करने पर ग्रामीणों ने बताया कि अब गैस का सिलेंडर 1500 रुपए तक में बिक रहे हैं तो इससे बेहतर लकड़ी जलाने की पारंपरिक विफल ही बचता है। हमारे राष्ट्र के धुर्तों को शायद कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हें तो पेट्रोल माफिया, अंबानी बंधुओं से कमीशन मिलना चाहिए। फिर चाहे करोड़ों लोगों के घर में रोटी बने न बने इनकी बला से। हम तो उस परम शक्ति से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इन दोनों राक्षस अनिल अंबानी-मुकेश अंबानी बंधुओं की देह मुक्तकरों ताकि करोड़ों लोगों को दो वक्त की रोटी मिलती रहे। इन राक्षसों ने तो पेट्रोल डीजल से लेकर सब्जी, गेहूं, दाल-चावल तक सब पर कब्जा जमाना और लूटने का खेल खत्म हो।

शिक्षालयों, समाज, सरकार, प्रसार माध्यम सभी हैं दोषी

पेज 8 का शेष

वह यही तो टीवी चैनलों को चाहिए होता है कि वही सरकार को वही प्रिंट मीडिया को सब दोहरा चरित्र जीना चाहता है और दूसरों पर उंगली उठाना, आखिर फिल्मों में खुला यौनाचार, कंडोम संस्कृति यौन स्वच्छदताओं धीरे-धीरे विकसित किसने किया और होने दिया यदि सरकार ने तो समाज ने क्यों बहिष्कार नहीं किया। भारत की न्याय प्रणाली के बारे में पूर्व राष्ट्रपति स्व. के आर नारायणनन ने कहा था, न्यायालय न्याय के मंदिर में जुए के अड्डे हैं। अपराधियों को सालों तक न्यायालयों में तारीखें बढ़ाकर बचाया जाता रहता है। सलमान खान ने कब 7 लोगों को कुचल के मारा था अभी भी शान से कमाई करता हुआ जिन्दगी गुजाररहा है। अनेकों सांसद विधायकों पर अपराध होने के बाद भी स्वयं जनता चुन कर सत्ता में बैठा देती है।

दामिनी बलात्कार में भीड़ अपराधियों को नशे की हालत में अपराध के कारण छोटीमोटी सजा ही दी जा सकती है। 20000 की हत्या लाख से ज्यादा घायल युनियन कांड में 26 वर्ष बाद फैसला, मात्र दो-दो वर्ष की सजा उस पर भी अपील का प्रावधान अर्थात हजारों की मौत से फर्क नहीं पड़ता न्यायाधीशों ने फिर बलात्कार कांड में क्या हो जाएगा, सभी दोषी हैं सरकार और समाज में छल 30 वर्षों से रोक लगाने की पहल नहीं होती है। जब परिणाम सामने आते हैं तो घड़ियाली आंसु बहाए जाते हैं। कैंडल मार्च निकाली जाते हैं। हर कोई भ्रम में जीना चाहता है।

पहले चलता है कहता है और करता है जब वह गति पकड़ लेता है तो चीखता चिलाता है हर कोई व्यक्ति जनता, समाज, और सरकार हर कोई कानून की बात करता है दूसरों के लिए पर स्वयं कोई कानून मानना नहीं चाहता । किसी को क्यों चिंता हो नहीं कि हम आनेवाली पीढ़ी के को क्या दे रहे हैं। उसके परिणाम क्यो होंगे और युवा पीढ़ी को भविष्य नहीं वर्तमान में ही जीने मरने को कहता है।

सो. रूस की तरह बिखरेगा अमेरिका

पेज 1 का शेष

वो विश्व व्यापार संगठन का मुद्दा उसके लिए फांसी की सजा बन गया। उसके अपने ही अमेरिकी कं. के आउट सोर्सिंग की चलत उसकी जनता को श्रम का अधिक मूल्य देने की अपेक्षा, उन कं. ने एशिया महाद्वीप के भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान के माध्यम से सस्ते श्रम का उपयोग किया। इससे न केवल बेरोजगारी बढ़ी वरन सेवाओं के मूल्य के बदले अमेरिकी मुद्रा का भी उसी अनुपात में पलायन भी हुआ।

अमेरिकी मूल कारोबार हथियार, टैंक, लड़ाकू विमान, जहाज, पनडुब्बियां जो कई गुना ज्यादों की मत पर दुनिया के देशों में बेचे जाते थे चूंकि सन् 2005 के बाद कोई बड़ा युद्ध न होने, आतंकवाद फैलाने, बढ़ाने, पालने-पोसने में भी उसकी हथियार बेंचने की नीति भी जगजाहिर हो जाने से उसकी भारी बदनामी हुई, इसलिए उस आतंकवाद वाली चाल जो सन् 1960 से चली आ रही थी, उसे वह भी बंद करना पड़ा, जिससे उसका हथियारों के बड़े-बड़े उद्योग भी ताले लग जाने से उसे भारी घाटा होने लगा, बेरोजगारी बढ़ती गई, युवा आक्रोशित होता गया।

प्रकृति का नियम है कि जो दूसरों को आंसू बांटता है, उसे प्रकृति उसे स्वयं आंसुओं से नहाना पड़ता है। अमेरिका ने सन् 1960-70 के दशक से जिस आतंकवाद के सहारे दुनिया को आतंकित किया था और अपने हथियार बेंच कर समृद्धि पाई थी, उस समृद्धि के दुष्परिणाम भी शीघ्र सामने आने ही थे, अमेरिकी प्रशासन ने स्कूली शिक्षा में भी स्वतंत्र यौनाचार को बढ़ावा दिया। स्कूलों में कंडोम बांट कर, स्वयं अपनी कब्र बनाते हुए युवा होती पीढ़ी को यौनाचार का रोग लगाकर नकारा निकम्मा बना दिया, युवा पीढ़ी स्कूली उम्र में ही शराब, कबाब और सबाब में डूब गई और जिस राष्ट्र की युवा पीढ़ी स्कूली शिक्षा से ही बर्बाद होने लगी हो उसका तो ये हाल होना ही था। जब युवा पीढ़ी ही बचपन में ही नकारी निकम्मी बना दी जाएगी तो देश का भविष्य क्या होगा? इसे ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। स्कूलों में कंडोम बांटकर स्वच्छद यौनाचार को बढ़ावा देने का षड्यंत्र वास्तविकता में कंडोम उत्पादक कं. का ही षड्यंत्र था, जैसे कंडोम उत्पादों की सोच थी कि स्कूलों में स्वच्छद यौनाचार की संस्कृति विकसित कर स्कूल शिक्षा से ही जीवनभर के लिए युवा पीढ़ी को अपना ग्राहक बनाना था, जिसका प्रचार-प्रसार उन्होंने एशियाई राष्ट्रों जिसमें प्रमुख रूप से भारत और चीन प्रमुख थे। स्कूलों में यौनशिक्षा की वकालत करवाकर करने का प्रयास किया था, परन्तु भारत और चीन की पुरातन सभ्यता के असर के कारण यह 10 वर्ष बाद पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका। अन्यथा यहां की युवा होती पीढ़ी भी अमेरिकियों की तरह घोर नकारा और निकम्मी अमेरिकी राष्ट्रपतियों जिसमें बिल क्लिंटन से लेकर ओबामा तक इस कारण ही भारतीय और चीनी युवाओं की जो अमेरिकी नौकरी पर कब्जा करने चले जा रहे हैं। पिछले 12-16 वर्षों से लगातार हड़पते रहे हैं और अमेरिकियों को पढ़ने और आगे बढ़ने की सलाह देते रहे हैं।

वैसे भी अधिकांश राज्यों में पूरे विश्व की मानव नस्लों के संकरो का निवास है। संकर प्रजाति का ये इतिहास खास है कि वो चालाक, निकम्मी और अय्याश प्रवृत्ति की होती है, जिसे हर काम में शार्टकट चाहिए होता है और बदले में मोटा धन। ये प्रवृत्ति में अमेरिकी युवाओं की बेरोजगारी का मूल कारण रही है। जिस पर और अपने प्रथम कार्यकाल में नियंत्रण नहीं पा सके। अब दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में ही भारी कर्ज का दबाव, अधिकांश घरेलू उपयोग की सामग्री का एशियाई राष्ट्रों से आयात जिससे चीन-भारत सबसे आगे है, जिससे खाद्य वस्तुओं के आयात से लेकर वस्त्र, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री आदि आते हैं। भुगतान संकट देश में स्वयं के उत्पादन का अभाव, दूसरी ओर विश्व के अनेक राष्ट्रों में पड़ी सेनाओं का खर्च ऐसी छोटी बड़ी सैकड़ों नीतियों से अमेरिका की रसातल को जाती अर्थव्यवस्था पर सुधार कर दूर नियंत्रण नहीं हो पर रहा है।

इन्हीं रीतियों-नीतियों से त्रस्त होकर अमेरिका के राज्यों ने अपने आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अलग होकर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत करा है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को स्वीकृत करना ही पड़ेगा। वैसे भी विश्व में जहां-जहां अमेरिकी फौजें पिछले 50-60 वर्षों से ज्यादा समय से पड़ी हैं, जिसमें ब्रिटेन और जापान भी है। ऐसे 90 से ज्यादा राष्ट्रों की सरकारें और उप राष्ट्रों के करोड़ों लोगों की आंखें भी अमेरिका की इस दादागिरी का अंत देखने के लिए बेचेन हैं ताकि उनकी सेनाओं को हटाया जा सके और यह अमेरिका के विखंडन बाद ही संभव होगा।

अमेरिका ने जैसे सोवियत को बिखेरा वैसे ही आज बिखेरने के लिए न केवल तल पूरा एशियाई राष्ट्रों की लगभग 350 करोड़ जनता के भी अरमानों में बसा है कि अमेरिका की बिखर जाए। अमेरिका के बिखने से दुनिया में अमेरिकी दादा गिरी का अंत हो जाएगा। राष्ट्रों पर प्रतिबंध, दबाव की राजनीति, आतंकवाद को बढ़ावा देने उसको पालने-पोसने और हथियार बेचने का षड्यंत्र भी स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों को मिल रही पाकिस्तानी सहायता जो उसे अमेरिका दे रहा है, वह भी आसानी से न केवल समाप्त हो जाएगी वरन् जो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दों को गर्म करके अपनी अरब देशों से मिलने वाली जकात के सहारे चल रही अर्थव्यवस्था को भी करारा झटका लगेगा।

जो हाल 80-90 के दशक में सोवियत रूस और उसके रूवल का हुआ, अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। रूसी घरेलू महिलाएं जीवन यापन के लिए मास्को की सड़कों पर निकलकर सरेआम वैश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर हो गई, अमेरिका के खंड-खंड बिखरने पर वही हाल होगा, जो वर्तमान में भी अमेरिका के ये ही हालात हैं। वह भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिलाएं बेरोजगारी से तंग आकर नाइट क्लबों, वैश्यालयों बारों तक में स्ट्रीय रोज कर रही जीवन यापन करने को मजबूर हो रही हैं।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सोवियत रूप से बिखरने था कम्युनिज्म वाद के चलते वहां की जनता के बोलने लिखने की पाबंदी की कंठा ने सोवियत रूप से 28 टकड़ेकर दिए, वहीं अमेरिका के बिखरने में पूंजीवादी शोषण से जनता के मस्तिष्क और दिलों में उठे आक्रोश के कारण अमेरिका बिखर जाएगा। यदि हमारे सत्ताधीश इन तथ्यों से सबक नहीं लेंगे तो पहले हम पूंजीपतियों के घोर उपजीकुंठा और पीढ़ा भी हमारे देश की जनता में विद्रोह कर देगी। इससे या तो पूरी तरह हमारा देश बहुराष्ट्रीय कं. की गुलामी के चंगुल में जकड़ जाएगा या हम भी सत्ताधीश या बड़े-बड़े दल-बल वाले नेता इसे भी खंड-खंड बिखेर कर पुनः राजे-रजवाड़े की पुरानी परम्पराओं में लौट जाएंगे। राष्ट्र की आजादी के समय नेहरू गांधी ने जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखी थी, वहीं सर्वश्रेष्ठ है, पर वर्तमान सत्ताधीश केन्द्र और राज्यों के अपने लाखों-करोड़ के कमीशन और वसूली के चलते सारी सार्वजनिक शासकीय नियंत्रण वाले विभागों यथा बिजली, पानी, सड़कें, दूराचार, परिवहन आदि को निजी क्षेत्र में सौंपकर जनता का घोर शोषण करवा रहे हैं। यही शोषण कुंठा यदि जनता ढंग से संगठित हो गई तो पहले इन बहुराष्ट्रीय कं. को फिर सत्ता के कानूनों के खिलाफ करेंगे जो उस राष्ट्र के फोर पतन का कारण बनेगा।

तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री पद के दावेदार मोदी की छवि बर्बाद करने का नाटक

कांग्रेस ने ही फेसबुक के माध्यम से भड़काया दिल्ली में दंगा

कहां से आये इंडिया गेट और विजय चौक पर पत्थर, गिट्टी, ईंट फेंकने के लिये रात में ट्रकों से भरकर दिल्ली पुलिस ने डलवाये थे

बलात्कार कांड को कांग्रेस द्वारा तूल देकर पूरे भारत में युवाओं में आक्रोश और प्रदर्शन करने के नाटक के पीछे मूल कारण था तीसरी बार गुजरात से मुख्यमंत्री बने युवाओं के परम प्रिय नेता जो भाजपा के भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं कि गुजरात चुनावों में जीत को युवाओं के दिलों से साफ करने उनका ब्रेनवाश करने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के भावी दावेदार बनाए रखने के लिए कांग्रेस को यह सारा षडयंत्र रचना बलात्कार कांड को तूल देना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ षडयंत्रों में भाजपा की महिला प्रधानमंत्री पद की प्रबल दावेदार सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी आदि के संयुक्त षडयंत्रों का परिणाम था, फिर युवाओं को उकसाना घेरना पत्थरबाजी को 7 दिन से ज्यादा तक नाटक चलाने का मूल औचित्त था, मोदी की युवाओं के मस्तिष्क में बनी छवि को साफ करना और जीत के जश्न को आंसूओं में बहा देना था। जिसमें फेसबुक के सहारे पक्ष और विपक्ष ने मिलकर सफलता पूर्वक अंजाम दिया।

भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण से दमन के गुस्से को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बगावत के सुरों को जानने और उनसे निपटने के लिए 25 दिसम्बर 1885 को अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने जिस कांग्रेस की स्थापना की थी, वर्तमान में 127 वर्ष बाद भी उस अंग्रेज की बनाई कांग्रेस भारतीयों के शोषण और दमन के गुस्से को शांत करने, बगावती सुरों को दबाने का काम ही कर रही है।

आजादी के बाद से भारतीय कांग्रेस ने भारतीय जनता का शोषण और नोंच-खसोट अंग्रेजों से ज्यादा तेज और तीरण कर दिया, जाते समय उनकी भारतीय कांग्रेस पार्टी ने पूछ ही लिया कि भारत पर 300 वर्ष कैसे शासन किया तो उन्होंने एक ही वाक्य में वह गुर बताया कि फूट डालो और राज करो, इसलिये कांग्रेसियों 50 वर्षों तक पूरे देश में येन-केन-प्रकरेण अपनी लूट, जालसाजियों को बेलाग अंजाम देने के लिये पूरे देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़काये, फिर 1980 के दशक से आतंकवाद का सहारा लिया। उसका खुलकर सदुपयोग कर सत्ता में बने रहे, घटनास्थल से पकड़े गये मुसलमान, उन्हें पुलिस, सीबीआई पकड़कर भी छोड़ दें, बाद में लंबी पूछताछ में हिन्दू संगठनों से जुड़े लोगों को प्रताड़ित करना, उन महिला साधुओं को जेल में पुलिस वालों द्वारा

सामूहिक बलात्कार करना प्रताड़ित करना, झूठे ही अपराधों पर कबूलनामा लिखवाना आदि के चरित्र को जनता वर्षों से देख रही है।

संचार साधनों के विकास और मीडिया इंटरनेट फेसबुक और ट्वीटर जैसी साइटों को जनता से वसूला गया। करों का अरबों रु. लुटाकर अपने विपरीत चलने वाले समाचारों को रोकना भ्रमपूर्ण समाचार फैला जनता का ध्यान बंटाने, अपनी महंगाई, गैस सिलेण्डरों की संख्या सीमित कर एफडीआई पर अपनी सरकार बचाने, कमीशनखोरी का आरोप छुपाने दबाव के लिये इस कांड को फेसबुक के माध्यम से लाखों युवाओं के फेसबुक पेज पर लगवा कर उकसाया गया। जिसके कांग्रेसी जालसाजों ने करोड़ों रु. अपने गुप्त एजेंडे से खर्च कर फेसबुक पर 19,20,21 दिस. तक माहौल बनाया गया, दिल्ली पुलिस की सीबीआई और गृह मंत्रालयों की टीम ने जानबूझकर खुलकर इस आग में घी डालकर पहले चारों तरफ से युवाओं को विजय चौक, इंडिया गेट मार्ग पर सुबह 9,10 बजे से 2 बजे तक एकत्र किया। फिर पूर्व नियोजित सत्ता के षड्यंत्र की नीति के अनुसार पुलिस चारों तरफ के बेरीकेट्स को खोलकर भीड़ को पुलिस ने जब तीन तरफ से घेर लिया फिर पानी की बौछारें छोड़ी गई और खुलकर लाठीचार्ज किया, टीवी चैनलों को ऐसा गर्म माहौल का इंतजार गुजरात के दंगों के बाद से ही था। चारों तरफ कैमरे ऐसे ही गरम लड़ाई झगड़े, मारापीटी, तोड़फोड़ की दृश्यावली ही टीवी की टीआरपी बढ़ाने, विज्ञापनें स्लॉट बंधने के लिये आवश्यक होती है वर्षों बाद मिली।

फेसबुक के जालसाज अच्छी से अच्छी बातों और विचारों को कचरे के टोकरे में डाल देते हैं। गंदे, अश्लील, नग्नता परोसने, खुला यौनाचार आदि के पन्नों पर लगे समाचार मिनिट भर में लाखों पन्नों पर पहुंचाकर विचार और टिप्पणीयां लगवा देते हैं। फेसबुक का प्रबंधन जिसके बारे में समय माया ने पूर्व में भी छापा था, हर प्रकार के कुकर्म करने मिनिट भर में धन मिलने पर लाखों प्रशंसक इकट्ठे करने का जो षड्यंत्र रचता है जिसके बारे में नियमित रुप से समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है, कांग्रेस से धन पाकर लाखों युवाओं की साइट पर प्रायोजित तरीके से दंगा भड़काने के लिये युवाओं को इकट्ठा किया गया। दिल्ली पुलिस, सीबीआई और अन्य एजेंसियों के साथ सरकार की भी हर गतिविधि पर पूरी नजर थी। मोबाइलों पर वार्तालाप, संदेश, बहुविधि संदेश, फेसबुक के माध्यम से 21-22 दिस. को युवाओं को विजय चौक, इंडिया गेट पर इकट्ठा करवाने से पूर्व दिल्ली पुलिस के ट्रक ही गिट्टी, पत्थर, ईंटे इकट्ठी करते थे। ताकि युवा उसका खुलकर दुरुपयोग करें फेंके, ये लट्ठ चलाये। समय बाधित समाप्त हो चुके आंसू गैस के गोले फोड़े, फिर करोड़ों रु. की खरीदी में भी कमाई का मौका मिलें। जनता-मीडिया का ध्यान कांग्रेसी महंगाई, गैस सिलेंडर, कसाब की फांसी का नाटक सब पर ध्यान हटा दिया गया। विजय चौक, इंडिया गेट पर दंगे चल रहे थे, उधर मनमोहन रूसी राष्ट्रपति के साथ बैठकर 22000 करोड़ के समय बाधित हथियारों के खरीदी के सौदे पर हस्ताक्षर कर रहे थे और भी कई बड़े षड्यंत्र पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कं. के साथ मिलकर लिये होंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भ्रष्ट, धूर्त, जालसाज कांग्रेसियों के लिये फेसबुक से दंगे भड़काने का यह पहला प्रयोग काफी सफल रहा।

कदम-कदम जालसाजों और वसूलीबाजों का अड्डा है, भोपाल से नाकों तक

पेज 3 का शेष

व्यापारियों की भी कर चोरी पूर्व से ज्यादा बढ़ी है, जबकि लाभ का अधिकांश हिस्सा बिचौलिए हड़प रहे हैं।

निःसंदेह समय माया के स्वकर निर्धारण और आईटीआर में हो रहे भ्रष्टाचार और शासन को पहुंचाई जा रही और हो रही क्षति के बारे में लगातार प्रकाशित करने के बाद ही शासन ने अंकेक्षण इंफोर्स में ए, आईटीआर जांच और औचित्य के लिए वृत्तिकर, वृहद कर दाता इकाई मनोरंजन कर आदि के लिए नई विभागीय शाखाएं खोली है। इसके वितरित स्वकर निर्धारण व्यापारियों को खुलकर कर चोरी करने का अप्रत्यक्ष आदतन अपराधी बनाने का कार्य ठीक-ठीक रहा है। इस लिए आवश्यक है कि 75 प्रतिशत व्यापारियों के खातों, लेन-देन, स्टाक, बिलों को वर्ष में दो-तीन बार नियमित जांच की जाए ताकि व्यापारियों में कर चोरी के प्रति भय बना रहे और बिचौलियों पर अंकुश बना रहे।

समय माया के संपादक अजमेरा ने सूचना के अधिकारी में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और यथार्थ जानने के लिए सूचना के अधिका में प्रधान सचिव को भी पत्र दिए थे, पर जो जितना बड़ा अधिकारी के उतना बढ़ा भ्रष्ट जालसाज और कानून का बलात्कारी मांगी जानकारी 06-07, 07-08, 08-09, 09-10, 10-11, 11-12 में लाभ दिया। पर कितना मल्टी प्लेक्स से मनोरंजन कर वसूल, कितनो को छूट का लाभ दिया, पर वहां बैठे धूर्त अपर सचिव फूलचंद राठौर जो सहा. लो.सू.अ. हैं। मंत्रालय को कानून को अपनी जेब में रखकर अपनी मनमर्जी से सूचना अधिकार में मनचाहे तरीके से कार्यवाही करते हैं। एक पत्र 16-7-12 को प्र.स.वा. कर मंत्रालय को भेजा गया जो 18-7-12 को वहां प्राप्त हुआ। 10वें दिन उसकी प्रति वा.कर मुख्यालय को जानकारी प्रेषित करने के लिए भेजी गई। जबकि वा. कर को मनोरंजन कर वसूलने का अधिकार 1 अप्रैल 11 से ही प्राप्त हुआ। उसके पूर्व वह आबकारी विभाग के पास वर्षोंह से था। जहां 1956 से ही भारी छुट-पुट स्तर का लाखों की कर चोरी का टाकिजों का इतिहास था। टाकिज वाले कर के साथ पूरी कीमत वसूलते अवश्य थे, पर सिनेमा की टिकिट पर पूरे टिकिट नहीं लगाते थे और कई बार टिकिट खत्म होने का बहाना बनाकर नहीं भी लगाते थे। पर जबसे मल्टी प्लेक्स टाकिजों का दौर शुरू हुआ और उन्हें 100 प्रतिशत मनोरंजन कर की 5 वर्ष की छूट मिली तब से कर चोरी और वसूली में करोड़ों रुपए का खेल भी शुरू हो गया और दर्शकों से भी भारी भरकम वसूली की जाने लगी। टिकिट का 20 प्रतिशत मनोरंजन कर अर्थात रुपए 500 की टिकिट पर रुपए 100 का मनोरंजन शुल्क हो गया है। श्री अजमेरा द्वारा जब यह पत्र 16-7-12 को प्रधान सचिव को भेजा गया तो वाणिज्यिक कर युक्त ने अधिकांश मल्टीप्लेक्स पर अग. 12 में छापे मारे तो सामने आया कि सभी मल्टीप्लेक्स एक तरफ 5 वर्ष की 100 प्रतिशत छूट का फायदा भी लेकर दर्शकों से 20 प्रतिशत मनोरंजन कर भी वसूल रहे हैं। जबकि यदि मनोरंजन कर वसूला गया है। तो मनोरंजन कर की शासकीय मद में जमा होना चाहिए जो कदापि वासपी योग्य नहीं है।

इसके विपरित अपर सचिव फूलचंद राठौर के ही आदेश दे दिए उपरोक्त आदेश स्पष्ट करते हैं कि कैसे आबकारी में मनोरंजन कर में केवल इंदौर मंगल एडलेब्स मल्टीप्लेक्स कांप्लेक्स इंदौर को कैसे रुपए 1,31,28, 764 कैसे दि. 30 80 को 50-50 प्रतिशत कर लौटा दिए गए। जबकि म.प्र. में 50 से ज्यादा मल्टीप्लेक्स में कितने आदेश से करोड़ भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार करने के कारण ही इसे आबकारी विभाग से हटाकर वाणिज्यिक कर को सौंप दिया गया। ताकि प्रधान सचिव के भ्रष्टाचार को पकड़ा न जा सके। यही कारण था कि अपर सचिव पीसी राठौर 06-07, 07-08, 08-09, 09-10, 10-11 की जानकारी के लिए मात्र वाणिज्यिक कर विभाग को लिखते रहें। अपील की गई तो एक ही अपील सुनवाई के लिए वाणिज्यि कर के मुख्यालय को भेजी गई। फिर प्रधान सचिव के विरुद्ध अपील की सुनवाई वाणिज्यिक कर के अपर आयुक्त व्ही के श्रीवास्तव ने एक तरफ ही कर डाली। अर्थात कानूनों की कैसे धज्जियां उड़ाई जाती है। आंख मीचकर कैसे की जाती है, जिसका छोटा सा उदाहरण है।

प्र.मं. को बदनाम करवा स्वयं प्र.मं. की दावेदारी

पेज 8 का शेष

अब बीमा धारकों की मेडिक्लेम पॉलिसी धारक को मालूम ही नहीं चलता कि उसके नाम से किसने उसके अस्पताल पहुंचने से पहले ही बीमे की राशि वसूल कर हड़प ली है। ये सारा खेल वो जालसाज शूकरों की फौज जिसे टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जाना जाता है। कब सारे बिल और अस्पतालों लेकर मेडिक्लेम धारकों के नाम से जो फर्जी तरीके से बीमा धारकों को भर्ती करके बिल लगाकर बीमा कम्पनियों से क्षतिपूर्ति वसूल करके बाले-बाले ही डकार कर लाखों करोड़ रुपए साल का बीमा कम्पनियों को पूरा देश भर में चूना लगा रहे हैं। लाखों वास्तविक मेडिक्लेम बीमा धारक सामान्य बीमा कं. के चक्कर लगाते रहते हैं। सामान्य बीमा कं. उनकी क्षतिपूर्ति इस टीपीए द्वारा डकार लिए जाने और राशि न बचने की पूरी बात कभी नहीं बताते और नियमों-कानूनों का बहाना बनाकर उन्हें भगा दिया जाता है।

ये वही चिटांबर है, जिसकी जालसाजियों के परिणाम स्वरूप 1986-87 से जब से स्व. राजीव की सरकार में वित्तमंत्री था लगभग देश में प्लांटेशन, गार्डन, डेयरी, कृषि आदि की लगभग 40000 कं. जिसमें गोल्डन फॉरेस्ट, सिंफनी, एनबी बाउंस परसराम युरिया प्लांटेंशन आदि ने जनता को धन दुगुना करने के नाम पर 40 लाख करोड़ का जनता से वसूल कर हड़प लिया गया। जब इसका पूरे देश में चारो तरफ भारी हो-हल्ला मचा तो सबके रास्ते हैदाराबाद में इसके घर पर खत्म हो रहे थे। वहां की पुलिस और प्रशासन ने इस चीटर का ही नाम लेकर सारे जांचकर्ता अधिकारियों को लौटा दिया। अधिकांश कं. का पैसा घूमफिर कर पास भी पहुंचा।

स्व. राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भी यह धूर्त था। 2004-09 के मनमोहन मंत्रिमण्डल में यह भी वित्तमंत्री और तब भी केन्द्र सरकार में कम से कम आयकर जमा हो और वहां के आयकर निरीक्षक से लेकर आयुक्त तक सब पैसा बंटोरे और आधा-आधा कर इसे भी पैसा पहुंचाए। इस मक्का ने आयकर विवरणी पत्रक ही इतना क्लिस्ट कर दिया ताकि उस प्रपत्र को भरने में बड़े-बड़े वकीलों को समझाने में आ गए। परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों अधिकारियों की उछलकर लॉटरी लगी। जबकि स्वयं बड़े अधिकारी उसकी जटिलताओं को ही नहीं समझ पाए। परिणाम यह हुआ कि अधिकारी ही रुपए 1 लाख करोड़ से ज्यादा रिश्वत डकार गए। गैस टंकियों पर नगद अनुदान खाद्य में नकद अनुदान आधार कार्ड का उद्देश्य भी यही है कि सरकार के धुर्तों को मालुम हो कि किसके खाते में कहां कितने पैसे पड़े हैं। उन्हें कैसे हजम करना है। किसे अनुदान देना है। किसे नहीं फिर ऊपर से चला अनुदान नीचे रुके 5 पैसे भी सही खाते में पहुंच जाए तो भी खुदा खैर करे फिर राजनीति, कर्मचारी, अधिकारी सबको लूटने का मौका मिलेगा। फिर जिसके वोट मिलेंगे उसी को अनुदान के नगद नोट मिलेंगे अन्यथा न वोट, न नोट। शिगुफा केवल नोट फॉर वोट। वोट नहीं तो काटे का नोट।

चीटांबर तो आस्तीन का सांप है, जिसकी बांह पर बैठेगा पूरा चूस जाएगा। यहां बैठेगा ये उक्त गुलिस्ता तबाह कर देगा।

इसके विरुद्ध मंत्री रहते हुए देश सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, बीमा कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं के शीर्ष पदों पर भारी भ्रष्ट और इसे अरबों रुपए का भुगतान करने वाले दक्षिण भारतीयों को बैठाकर खूब जालसाजियां करवा कर धन लग गया। उसकी भरपाई करने और घोटाले से बचाने के लिए सभी ने अपने सेवा शुल्क 300 प्रतिशत तक बढ़ा दिए। मीडिया भारत का हो या विदेशी या अन्तराष्ट्रीय, सब धन के गुलाम हैं। पैसा खर्च करो तथा प्रधानमंत्री की बदनामी बयां तारीफ सब पैसा फेंको और तमाशा देखो, का खेल है।

साप्ताहिक समय माया

24 घंटे टीवी चैनलों, फिल्मों, इंटरनेट साइटों पर परोसा जा रहा यौनाचार

शिक्षालयों, समाज, सरकार, प्रसार माध्यम सभी हैं दोषी

विकृतियां, फूहड़, यौनाचार व्यवसाय बन चुका है परिणाम ही तो है

पूरे विश्व में दामिनी के सामूहिक बलात्कार और मौत का मातम मनाया गया। कोई भी इस तीमत्स कांड की जड़ों में जाना नहीं चाहता। न सरकार, न समाज, क्या हुआ इस संस्कारी देश की धरती को जहां नारी मां के रूप में देवी के रूप में पूजी जाती है। समाज की नसों में फिल्मों द्वारा, टीवी चैनलों द्वारा परोसी जा रही नग्नता यौनाचार, वस्यहीनता को समाज ने क्यों स्वीकार किया। उल्टे ही वही समाज फिल्म इंडस्ट्री डर्टी पिक्चर को पुरस्कार दे रहा है। हीरोइन की नायिका और उसकी नग्नता और यौनाचार को सिर पर बैठा रहा है और उस गंदगी को कला का नाम दे रहा है आइटम सांग हर फिल्म का अनिवार्य व्यवसायिक अंग बन चुका है। तब कहां सो रहा था ये समाज जब फिल्मों में सैकड़ों आपराधिक पुरुषों के बीच नायिका वस्त्रहीन हो आइटम सांग फिल्मा रही थी। फिर करोड़ो युवाओं के बीच फिल्म दिखाई जा रही थी। तब ये युवा पीढ़ी ऊंघ रही थी, तब महिला संगठनों, समाज के वरिष्ठजनों ने पूरे देश में इसके विरोध में आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों फिल्म सेंसर बोर्ड ने फिल्मों ने दिखाए जा हिंसक यौनाचार पर सरकार की ओर से कैची क्यों नहीं चलाई फिर यदि फिल्म सेंसर बोर्ड कैंची चला देता तो यही महान महानायक होने का दंभ भरने वाले अमिताभ, महेशभट्ट, पूजा भट्ट, एकता कपूर व सैकड़ों कानूनविद कलाकार, महिलाएं संगठन सरकार या कला की अभिव्यक्ति पर प्रति बंध का आरोप लगाते। इस राष्ट्र की जनता, समाज, सरकार का यही दोहरा चरित्र उसका सबसे बड़ा अभिषाप और सहस्त्रों वर्षों की गुलामी का कारण भी रहा है। फिर जितने प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। उनकी यर्थाथ मानसिकता का परिचायक उनका अपना मल्टीमीडिया मोबाइल ही है। खोलकर देख लीजिए 10-12 वर्षों के छात्र-छात्राओं के मल्टीमीडिया मोबाइल की गैलरी में कितनी यौनाचार के चल चित्रों का भंडार पाया जाएगा और यह सब स्कूल की माध्यम उच्च मध्यम, उच्च वर्गीय घरों में पले बड़े छात्र-छात्राओ के शौक और आधुनिकता का हिस्सा है। उनके माता-पिता अपनी मौज मस्तियों में व्यस्त रहते हैं। उनके पास समय नहीं कि वो अपनी युवा होते पुत्र-पुत्रियों से जीवंत सम्पर्क घर में और घर के बाहर बनाए और जाने की तो पढ़ाई के अतिरिक्त कहां कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे समय में वो अपनी महानता दिखाते हैं और उन्हें पैसा और उनका आवश्यकता पूरी कर अपने कृतव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। आखिर जिन बदमीजों ने ये कांड किया वो भी तो किसी मां की कोख से जन्मे ही होंगे। उनका कोई बाप होगा? ये संस्कारों का ही परिणाम है जहां तक ये स्कूल वाले कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। उनके शिक्षकों और प्राचार्यों के अपने चरित्र बयां है? वो देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सभी निजी स्कूल विद्यार्थियों के घोर शोषण में हर प्रकार से लिप्त है। न केवल पुरुष वरन् महिला शिक्षिकाएं भी घोर शोषण कर रही हैं। जिसकी खबरें आए दिन समाचार पत्रों में छापी जा रही है। धीरे-धीरे पुरुषों के यौन शोषण की 0.5 प्रतिशत सच्चाइयां सामने आने लगी है।

आखिर चारों तरफ यौनाचार, यौन उत्तेजना कर प्रदर्शन और वातावरण फिर हाथों में मोबाइल, लेपटाप जिसमें विश्व के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर और उत्तरी से दक्षिणी छोर तक होने वाले यौनाचार और यौनाचार पूर्ण अपराधों की चल चित्रावलियों से कब तक युवा अछूता रहेगा। उस पर चारों तरफ उपलब्ध शराब के साथ ही भांग, गांजा, चरस, अफीम से हजारों गुना तेज औषधियां, जूस, सिरप, चाकलेट आसानी से उपलब्ध हैं। हर गली चौराहे पर ऐसे सारे ड्रग्स माफियाओं का स्वयं महीना खाकर नारकोटिक्स, आबकारी पालता आ रहा है। ऐसे सभी माफिया पुलिस के संरक्षण में ही रहकर युवा पीढ़ी को नशे का आदि बना रहे हैं, जिसके जीभ पर रखते ही साथ या इंजेक्शन से लेते हैं साथ मन मस्तिष्क और शरीर उत्तेजनक हो एंठने लगता है फिर क्या होगा सोचा जा सकता है? फिर चारों तरफ खुले पब, बार, डिस्को थेक, फार्म हाउस, हुक्का लाउंज, नेटबारों में क्या हो रहा है। आखिर जो लड़कियां, महिलाएं इन बारों पबों, हुक्का लाउंजेस, नेट कैफे, फार्म हाउसेज, डिस्को थेक में जा रही हैं। आखिर उनके मां-बाप क्या कर रहे हैं। फिर अब जब हर लड़की के लिए 2-4 ब्यावफ्रेंड रखना फैशन बन चुका है। जहां आपस में सहेलियों में ये होड़ लगी हो कि किसके कितने ब्यायफ्रेंड है। दो-तीन मोबाइल रखना फैशन है तो किसके लिए कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करने जा रही है या रोमांस की शिक्षा हो रही है तब मां बाप क्यों आंखे मूंदे रहते हैं।

यूरोप की तरह यहां भी नग्नता का उद्योग दिन दूनी रात चौगुनी गति से क्यों फलफूल रहा है। यूरोप की वैश्याओं से कहीं ज्यादा गंदी औरत सनी लियोन आती है तो युवाओं को भले ही कोई चाहत हो न हो, फिल्म उद्योग करीना, दीपिका, सोनम व अन्य सैकड़ों कई उसके नग्नता गंदे यौनाचार के वीडियो इसलिए देखती हैं कि उससे ज्यादा कितनी गंदगी और यौनाचार पर्दे पर दिखा सकती है। जिसकी खबरों से सारे अखबार भर जाते हैं। टीवी चैनल्स इनका वीडियो देश की युवा होती पीढ़ी और घरेलू महिलाएं जो सबसे ज्यादा टीवी देखती हैं परोसने के लिए होड़ मच जाती है। एकता कपूर, पूजा भट्ट जैसी महिला डायरेक्टर उस पर फिल्म बनाने के लिए पतक पांवड़े बिछाते हैं। फिर जब दामिनी वहीं उत्तेरित वर्ग शराब के नशे में मदहोश होकर बलात्कार कर देता है। तो फिर वही मीडिया उसकी सांसे और धड़कन देश को सुनाता है, भीड़ लगाता हैष सरकार में बैठे धुर्तों व पुलिस से मिलकर पहने उन्हें इकट्ठा करती है उनके लिए गिट्टी, पत्थर, ईंट इकट्ठे करती है, जहां रखते होते हैं। उस ओर धकेली है और फिर पत्थर गिट्टी बरसाने के लिए मजबूर करती है।

(शेष पेज 6 पर)

चीटांबर की जालसाजियां - राष्ट्र का करोड़ों लुटाकर

प्रधानमंत्री को बदनाम कर, स्वयं की दावेदारी

अनुदान का नगद भुगतान का शिगुफा अरबों रुपए डकारने की चाल

भारत सरकार को चला रही डकैत कांग्रेस और सहयोगियों का गिरोह वैसे तो राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों से लेकर जनता के नाम, राष्ट्र और राष्ट्र की सम्पत्तियों को गिरवी करने, बेचने बदले में अरबों करोड़ों रुपए का कमीशन जनता का गुलाम बनाने के षड्यंत्रों को समय माया वर्षों से न केवल समय माया समाचार पत्र वरन् समय माया डॉट कॉम की साइट पर लोड कर जनहित में अपने शैशनकाल से ही सिर पर कफन बांध प्रकाशित और प्रसारित करता रहा है। जिसे पहले पाठक साथी और सहयोगी केवल कपोल कलित समझते थे। उसका वर्षों बाद यथार्थ सामने आया वहीं सच हमने वित्तमंत्री गृहमंत्री फिर वित्तमंत्री पद पर वर्तमान के पी. चिदंबरम जनता, शासन के साथ तो छल करता ही रहा है। यहां तक कि उसने चुनाव भी जालसाजियों से ही जीता, जिसके विरुद्ध तलिम मुख्यमंत्री जयललिता ने न केवल जोर-शोर से मामला पूरे देश में उठाया वरन् उच्च न्यायालय में भी लगाया।

हमारे राष्ट्र की न्यायालयीन व्यवस्था के बारे में हमारे ही राष्ट्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व. आर. नारायणन ने 25 जनवरी 2000 को जो टिप्पणी की थी, 'हमारे न्यायालय के मंदिर नहीं, जुए के अड्डे हैं, जो जितना बड़ा दांव खेलेगा उसे उतना न्याय मिलेगा।' से समझा जा सकता है जो पर्याप्त स्वयं सिद्ध व्याख्या है। भारतीय जिला न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की जो आजादी के बाद इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य की। फिर कानून की परिभाषा कानून की पुस्तकों में कुछ भी आदर्शवादी व्याख्या हो वास्तव में कानून धुर्तों के

बनाए शब्दों के मायाजाल है जो अपने पोषण और निरीहों के शोषण के काम आने वाले शाब्दिक हथियार हैं। आखिर पी. चिटांबर केन्द्रीय मंत्री था, इसलिए फैसला उसके पक्ष में हो गया केन्द्र की सहमति और राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां पदोन्नति होती है। अभी 3-4 माह पहले अन्तरराष्ट्रीय मीडिया ने भारत के प्रधानमंत्री की जो भारी आलोचनाएं की थी। बाद में दिस की 1-2 को इकानॉमिस्ट अन्तरराष्ट्रीय पत्रिका ने फिर चीटांबर को प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का दावेदार और श्रेष्ठ वित्तमंत्री बताया। पूरा चीटांबर के अन्तरराष्ट्रीय मीडिया पर खर्च किए भारतीय धन के षड्यंत्रों के परिणाम का हिस्सा था। चीटांबर अच्छी तरह जानता है कि राहुल गांधी के रहते भारत में उसके प्रधानमंत्री बनने के अवसर बिल्कुल नगण्य है। इसलिए उसने पहले वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन को बदनाम करवाया। उस मामले को महीने-दो महीने ठंडा किया और फिर अपना नाम उछलवाया ताकि भविष्य में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने से स्वमेत मना कर दें तो अरयो चीटांबर की दावेदारी पुख्ता हो सके। चीटांबर ने वित्तमंत्री रहते हुए भारत की राष्ट्रीयकृत बैंकों को रुपए 16000 करोड़ का पैकेज दिलवाया था। सन् 2006-07 में आखिर क्यों? क्योंकि इन हरामखोर जालसाज कांग्रेसियों ने जिन उद्योगपतियों से अरबों रुपए का कमीशन उकारा था। उन अधिकांश उद्योगपतियों पर बैंकों का जो अरबों रुपए का कर्ज था उस कर्ज को कानूनी शब्दों का मायाजाल फैलाकर माफ तो करवा लिया उसकी भरपाई करने के लिए रुपए 16000 करोड़ का पैकेज दिया गया था। बीमा व्यवसाय में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश में भी अरबों रुपए का कमीशन डकार कर ही आज्ञा दी गई तुम हमें दे, दो फिर देश को लूटो। कोई गल नहीं, जबकि हाल ही में बजाज एलियांज कम्पनी ने रातों रात कारोबार समेट कर पैसा हजम करके भाग गई। निजी बीमा कम्पनियों की कमाई और राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों को डुबोने, बीमा धारकों के नाम से सामान्य बीमा शासकीय बीमा उपक्रमों को करोड़ों रुपए से वसूलते हजम करने के लिए ही इस चीटर ने तृतीय पक्ष प्रशासक की भूमिका में पूरे देश में अपनी ही लगभग 20 से कम्पनियों को उतार कर अरबों रुपए डकारने का खेल सन् 2006 से इसने ही शुरू करवाया। (शेष पेज 7 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803